● वर्ष-6
● अंक-96
रायपुर, बुधवार
18 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> लौकी तोरई से ऊब गए...

नफरत के जाल में फंसे समर्थक

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा पलटवार किया। यह प्रतिक्रिया तब आई जब उनके माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण रिश्ते को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया गया। राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण, बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत का एक ऐसा जाल बुना हुआ है, जो उन्हें प्यार को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोकता है। अपनी आलोचना को और विस्तार देते हुए, उन्होंने पारंपरिक मूल्यों पर आधारित अपने दार्शनिक मिशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, एक सच्चे हिंदू के रूप में, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनत्व की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें। सत्यम शिवम सुंदरम।



क्या है पूरा मामला?

ये टिप्पणियां नई दिल्ली में आयोजित संस्मरण के आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संबोधन के बाद आईं, जहां उन्होंने अपने माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण पलों को याद किया। राहुल गांधी ने कहा, अचानक, हमने अपनी मुख्य आधार (इंदिरा गांधी) को गोली खाते देखा, और फिर हमने अपने सबसे बड़े आधार (राजीव गांधी) को चिथड़े-चिथड़े होते देखा। मेरी मां के साथ अक्सर इस बात पर बहस होती है। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के। अगर आप उनसे पूछें, पापा की मौत के समय क्या हुआ था? तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। किताब में आपने जो पढ़ा है, उसे मेरी बहन और उन्होंने मिलकर

मोदी ने आसियान देशों के सामने रखे 8 प्रस्ताव समुद्री सुरक्षा से साइबर अपराध तक पर जोर

मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया।

इस दौरान उन्होंने भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे। वहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ क्वाड नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में ट्रंप ने पीएम मोदी को टफ मैन बताया, जबकि मोदी ने क्वाड के साथ मनीला के पुराने रिश्तों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रस्ताव रखा।



ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया मजबूत शख्स

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टफ गाइ (मजबूत शख्स) बताया। ट्रंप की यह टिप्पणी दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सामने आई। वहीं, पीएम मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में निवेश, बुनियादी ढांचे, नवाचार, सेमीकंडक्टर और आधुनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, डिजिटल तकनीक, संस्कृति और पर्यटन जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई।

मोदी ने उठाया जमीन पर रखा तिरंगा, ट्रंप बोले- संभालकर रखिए

फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। बैठक में शामिल होने के लिए जब क्वाड देशों के नेता पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जगह बताने के लिए जमीन पर रखा भारतीय तिरंगा उठा लिया। यह झंडा बैठक स्थल पर भारत की जगह पहचानने के लिए स्पॉट मार्कर के तौर पर लगाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को तिरंगा उठाते देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसे संभालकर रखिए। इस दौरान का वीडियो व्हाइट हाउस की ओर से जारी किया गया है।



पुल से गिरी बस, 9 की मौत, 26 घायल

देहरादून। टिहरी जिले में गूलर घाटी के पास मंगलवार सुबह हुए बस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। घायलों में से भी 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बस हरिद्वार से चमोली कर्णप्रयाग जा रही थी। हादसे के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया।

मंगलवार को सुबह करीब 4.30 बजे यात्री बस गूलर बाजार के पास अनियंत्रित होकर गूलर पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की ब्यासी पोस्ट से उपनिरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए ढालवाला और एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय से भी अतिरिक्त टीमें भेजी गईं।

दुर्गम रास्ते और कठिन परिस्थितियों के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को स्ट्रेचर की मदद से सड़क तक पहुंचाया गया। यहां से एंबुलेंस के जरिये उन्हें अस्पताल भेजा गया। हादसे में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो यात्रियों ने ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया।

माफी दिल से मांगें, दिमाग से नहीं; कहा- आप अनुभवी नेता, संयम रखें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को नसीहत दी है। आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। कोर्ट ने राउत को अनुभवी नेता और सांसद बताते हुए सार्वजनिक बयान देते समय संयम बरतने की सलाह दी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबी) की ओर से पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका से जुड़ा है। दोनों पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, न कि दिमाग से। उन्होंने राउत से कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता और सांसद हैं। अदालत उनके भाषण पहले से सुनती रही है। वह खुद पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में किस तरह का संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि सम्मानजनक पद पर बैठे व्यक्ति से अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।



हैदराबाद में कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के एक नेता द्वारा विवादित नारे लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विदेशी नेताओं द्वारा भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने विदेशी प्रतिनिधियों के भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने, समिट की जांच कराने और तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। याचिका में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों और वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे पर सवाल उठाए गए हैं।

इंडिया गठबंधन की याचिका पर टली सुनवाई

चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख नौ दिसंबर तय की है। विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है। बता दें कि सोमवार, 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था।

बांग्लादेश की हिरासत में बीएसएफ का एक जवान, मेघालय में सीमा के पास हुई घटना

नई दिल्ली। बांग्लादेश के जवानों ने मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ के एक जवान को हिरासत में ले लिया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को हथियारबंद बीएसएफ जवान अनजाने में दूसरी तरफ चला गया था। यह घटना मेघालय के जोवाई इलाके में हुई, जो बांग्लादेश के सिलहट जिले के सामने पड़ता है। अधिकारियों के अनुसार इस इलाके में दोनों तरफ के पर्यटक आते-जाते रहते हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो का भी संज्ञान लिया है। इन वीडियो में बीजीबी के दो जवान और कुछ स्थानीय लोग उस भारतीय जवान के साथ दिख रहे हैं। जवान के पास एक वॉकी-टॉकी सेट है और उसके शरीर पर एक आईएनएसएएस राइफल तथा एक पंप-एक्शन गन लटकी हुई है।



जवान की वापसी में जुटे अधिकारी

अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ जवान को वापस लाने के लिए एक 'फ्लैग मीटिंग' की जा रही है। बीएसएफ देश के पूर्वी हिस्से में 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

आईएएस-आईपीएस अफसरों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने इनके महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, अब अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में बताया गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया था। अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत ये संशोधित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगी। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जुलाई 2026 से नकद किया जाएगा। ह्ब की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के तहत आहरित वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

पारादीप तट पर डूबने वाला था जहाज तटरक्षक बलों ने 27 की बचाई जान

पारादीप। ओडिशा तट के पास पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) और भारतीय तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) ने मुसीबत में फंसे एक जहाज के 27 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया, जिससे एक बड़ी समुद्री आपदा टल गई। यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) से मिली एक जरूरी सूचना के बाद यह संयुक्त अभियान शुरू किया गया। एससीआई ने बताया था कि जहाज में पानी भर रहा है और उसका प्रोपेलर शाफ्ट खराब हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि एमवी विश्व उदय नाम के इस जहाज को सुरक्षित खींचकर (टो करके) मंगलवार सुबह बंदरगाह की बाहरी सीमा के पास लंगर डाल दिया गया।

पीपीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, समुद्री बचाव: पारादीप पोर्ट अथॉरिटी द्वारा सफल बचाव अभियान! पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने एससीआई लिमिटेड के एक तत्काल अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एमवी विश्व उदय के लिए एक समन्वित बचाव अभियान चलाया। इस जहाज पर 27 क्रू सदस्य सवार थे।

चोरी की गई कलाकृतियां तलाशने के लिए संस्कृति मंत्रालय बनाएगा विजुअल लाइब्रेरी

नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने चोरी हुई प्राचीन कलाकृतियों की एक 'विजुअल लाइब्रेरी' बनाने और कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से विदेशों में मौजूद संदिग्ध कलाकृतियों की वैज्ञानिक तरीके से तुलना करने की योजना बनाई है। संस्कृति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे नीलामी के दौरान चोरी की गई कलाकृतियों की पहचान कर समय रहते उनकी बिक्री रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कर्तव्य भवन में सोमवार को पत्रकारों से कहा कि मंत्रालय चुराई जा चुकी प्राचीन वस्तुओं का एक ऐसा दृश्य संग्रह तैयार करने पर विचार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल विदेशों में भारतीय मिशनों और संस्थानों को इन कलाकृतियों की पहचान करने में मदद देने के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध कलाकृतियों की तस्वीरों, उनके आकार और मूल वस्तुओं पर मौजूद विशिष्ट निशानों का मिलान किया जा सकेगा। अग्रवाल ने कहा, ''यदि आपके पास चोरी हुई वस्तुओं की एक विजुअल लाइब्रेरी है।

होर्मुज में गैस टैंकर पर मिसाइल अटैक, 24 भारतीय थे सवार

नई दिल्ली। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को बताया कि 16 नवंबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर तारा गैस पर मिसाइल से हमला किया गया। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। सभी 25 क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। एक्स पर एक पोस्ट में सोनोवाल ने कहा कि अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा 16 नवंबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर तारा गैस पर मिसाइल से हमला हुआ, जिस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। सभी 24 भारतीय नागरिकों सहित कुल 25 क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटों में वहां कम से कम चार तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरानी नौसेना ने बताया कि पूर्वी होर्मुज जलडमरूमध्य में एक नौसैनिक खदान (नेवल माइन) से टकराने के बाद चौथे टैंकर में आग लग गई।

दिखा चीन का गुप्त शेनलोंग स्पेसप्लेन

वॉशिंगटन। अमेरिकी खुफिया विभाग की जारी की गई एक तस्वीर ने चीन के गुप्त स्पेसप्लेन शेनलोंग को लेकर दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस तस्वीर में शेनलोंग के पेलोड बे के दरवाजे खुले हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बाद दोबारा इस्तेमाल होने वाले स्पेसप्लेन के संभावित सैन्य इस्तेमाल पर चर्चा तेज हो गई है। इनमें कक्षा से तेजी से हमला करने की क्षमता के साथ आपातकालीन मदद और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जैसे इस्तेमाल भी शामिल हैं।

यह यान दिखने में अमेरिकी सेना के बोइंग निर्मित एक्स27बी जैसा है। एक्स27बी बिना चालक दल वाला एक ऐसा स्पेसप्लेन है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रस्तावित स्पेसप्लेन समूह का सैन्य अभियानों पर असर पड़ सकता है।

चीन के विशेषज्ञ यह स्टडी कर रहे हैं कि ऐसे 40 विमान कैसे पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। बता दें कि कक्षा में पहले से मौजूद इन वाहनों को कमांड मिलने के बाद पृथ्वी से लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय वे कक्षा में सही मौका मिलने पर सीधे नीचे उतरना शुरू कर सकते हैं। जमीन से लॉन्च की जाने वाली पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत ये ऑर्बिटल वाहन अलग अलग दिशाओं से लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं और वायुमंडल में उड़ान भरते समय अपनी दिशा बदल सकते हैं।

युगे युगेन म्यूजियम में दिखेगी डांसिंग गर्ल और निजाम के आभूषण, 2027 में खुलेगी पहली गैलरी

नई दिल्ली। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा 'डांसिंग गर्ल', निजाम के बेशकीमती आभूषण और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय की कुछ मूर्तियां दिल्ली में बन रहे युगे युगेन भारत संग्रहालय की 'अलंकरण' दीर्घा का हिस्सा होंगी। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने यह जानकारी दी। कर्तव्य भवन में सोमवार को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल ने कहा कि नए संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से ली जाएंगी और राष्ट्रीय संग्रहालय की दीर्घाओं का भी नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपथ स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत हटाया नहीं जाएगा और सरकार ने इसे राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। करीब 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस संग्रहालय में पांच हजार साल से अधिक पुरानी भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी लगभग दो लाख भारतीय और विदेशी वस्तुएं मौजूद हैं। इसकी आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई, 1955 को रखी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसरों के पुन: उपयोग के जरिए युगे युगेन भारत संग्रहालय विकसित करने को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना पर अनुमानित 3,230 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाले इस संस्थान में आठ विषयगत दीर्घाएं होंगी, जिनमें पांच हजार साल से अधिक की भारत की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाया जाएगा।



परियोजना को 2031 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसकी पहली दीर्घा 'अलंकरण' नॉर्थ ब्लॉक में विकसित की जा रही है, जिसके 2027 के उत्तरार्ध में आम लोगों के लिए खुलने की उम्मीद है। अग्रवाल ने कहा, ''राष्ट्रीय संग्रहालय इतिहास का संग्रहालय बना रहेगा, जबकि युगे युगेन भारत संग्रहालय सभ्यता को समर्पित होगा।

दोनों की विषयवस्तु में स्पष्ट अंतर होगा।'' उन्होंने बताया कि नए संग्रहालय के लिए देशभर के संग्रहालयों से वस्तुएं जुटाई जा रही हैं। संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि नए संग्रहालय की पहली दीर्घा में एक हजार से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तिजोरियों में रखे निजाम के आभूषण, राष्ट्रीय संग्रहालय के तक्षशिला के आभूषण, लघु चित्रकला संग्रह के कुछ नमूने, भारतीय संग्रहालय की मूर्तियां और गांधार कला की मूर्तियां शामिल हैं।

प्रयागराज संग्रहालय से भी कुछ वस्तुएं लाई जाएंगी। करीब 4,500 साल पुरानी 'डांसिंग गर्ल' प्रतिमा को 'अलंकरण' दीर्घा का प्रमुख आकर्षण बनाया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि यह प्रतिमा उस दौर में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों और सजावटी वस्तुओं की जानकारी देने वाली सबसे शुरुआती कलाकृतियों में से एक है। अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय संग्रहालय में फिलहाल केवल 10 प्रतिशत वस्तुएं ही प्रदर्शित हैं।

जबकि शेष 90 प्रतिशत भंडारण में रखी हैं। उन्होंने कहा कि पहले युगे युगेन भारत संग्रहालय की दीर्घाओं को तैयार किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय की विषयवस्तु के अनुरूप वस्तुओं का नए सिरे से चयन और प्रदर्शन किया जाएगा।

नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय समेत केंद्र सरकार के कई कार्यालय स्थित थे, जबकि साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के कार्यालय थे। इन मंत्रालयों को इंडिया गेट परिसर के पास नवनिर्मित कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित किया जा चुका है।

सर्च ऑपरेशन में सफलता : कांकेर के कोयलीबेड़ा में मिला नक्सल डंप

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान जवानों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अहम सफलता मिली है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मोदेमरका और मिच्चेबेड़ा फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों का डंप मिला है। इस डंप में हथियार, विस्फोटक और नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले सामान मिले हैं।

कांकेर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम इलाके में सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इस दौरान जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल डम्प का पता चला। तलाशी लेने पर एक भारमार बंदूक, करीब एक किलोग्राम संदिग्ध आईईडी मैकेनिज्म, लगभग एक किलोग्राम गन पाउडर और दो डेटोनेटर बरामद किए गए।



सुरक्षाबलों की बीडीएस टीम ने आईईडी और विस्फोटक को मौके पर नष्ट कर दिया। नक्सल प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की संयुक्त सर्चिंग लगातार जारी है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है।कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्च अभियान बस्तर रेंज के आईजी बद्री नारायण मीणा के निर्देश पर चल रहा है। यह सर्च ऑपरेशन बीएसएफ डीआईजी दीपक तिवारी, कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा और 40वीं वाहिनी बीएसएफ के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हो रहा है। कांकेर एसपी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा।

कटघरे में खड़े होकर सीजीएम को जान से मारने की दी धमकी, एफआईआर दर्ज

मुंगेली। मुंगेली जिला न्यायालय में पेशी के दौरान चोरी के आरोपी ने जमकर बवाल काटा। ट्रक चोरी के आरोप में भगतराम राजपूत को सरगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 16 अक्टूबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान नाम पूछने पर बदतमीजी करते हुए कटघरे से कूदकर डायस पर चढ़ गया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी और कांच के फ्रेम को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्रस्तुतकर्ता शत्रुघन कुमार बेलदार ने थाना पहुंचकर शिकायत दी, जिसके आधार पर स्नढ्डक्र दर्ज कर ली गई है।



दरअसल, 16 नवंबर को सरगांव थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 189/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के मामले में गिरफ्तार आरोपी भगतराम राजपूत (25 वर्ष) को शाम करीब 4:30 बजे रिमांड के लिए मुंगेली जिला न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिसकर्मी आरोपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए ले जा रहे थे, तब उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने लगा। शिकायत में बताया गया कि आरोपी भगतराम राजपूत ने पीठासीन अधिकारी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि 'तू मेरे को जेल भेजेगा बे।' इसके बाद वह कटघरे से छलांग लगाकर पीठासीन अधिकारी के सामने लगे कांच के फ्रेम के पास पहुंचा और उसे जोर-जोर से तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी के साथ न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा किए गए कृत्य काफी अपमानजनक है। घटना से सभी आहत हैं। वहीं पीठासीन अधिकारी के कांच के फ्रेम को तोड़ने का प्रयास करना जान से मारने के आशय को दर्शाता है। आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराधिक कृत्य के संबंध में कार्रवाई होनी चाहिए। सरगांव थाना में चालक रामखिलावन कुर्मी ने ट्रक चोरी होने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि 15 नवंबर को वह गेवरा खदान से 38।650 टन कोयला कोयला को ट्रेलर लोडकर रायपुर वंदना प्लांट के लिए निकला था। सुबह 6 बजे सरगांव पथरिया मोड़ के पास वाहन खड़ा कर के दुकान में चाय पीने चले गया, लेकिन जब वापस आया तब ट्रेलर गायब मिला। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान ट्रेलर में लगे जीपीएस सिस्टम के लोकेशन के आधार पर मदकू गांव में घेराबंदी कर मदकूद्वीप चौक के पास वाहन पकड़ा गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम भगतराम राजपूत बताया। इसके बाद वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

फिलहाल मामले में शिकायत के बाद मुंगेली पुलिस ने आरोपी भगतराम राजपूत के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 296, 351 (3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

आंगनबाड़ी वर्कर्स ने खोला मोर्चा

बस्तर। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए तीन दिवसीय हड़ताल शुरु कर दी है। आंगनबाड़ी वर्कर्स शहर के कृषि मंडी में उपस्थित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आगामी 11-12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन करने और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है।

आंगनबाड़ी संघ की प्रमुख तीन सूत्रीय मांग हैं। जिनमें नियमितीकरण, नियमितीकरण से पहले 30 हजार रुपए मानदेय और आयु सीमा समाप्त करके कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर में लिया जाए और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त राशि की मांग शामिल है।

संभागीय अध्यक्ष प्रेमवती नाग का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्य बढ़ गया है। लेकिन समय पर मानदेय नहीं मिलता है। शिक्षक अपनी ड्यूटी 10 बजे से 4 बजे तक करते हैं। उन्हें 70 हजार से 1 लाख रुपये तक वेतन मिलता है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उनमें भी उन्हें केवल 10 हजार मिलता है।



उसमे भी 4500 रुपये के लिए इंतजार करना पड़ता है। साथ ही मानदेय से ही बैठक, और कार्यालयीन कार्यों के लिए ईंधन डलवाया जाता है। इंटरनेट संबधी कार्यों के लिए भी रिचार्ज कम दिया जाता है।

प्रेमवती नाग ने कहा कि आगामी 11-12 दिसम्बर को महापड़ाव के अंतर्गत राजधानी रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जाएगा।आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाहे आंदोलनकारियों के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई क्यों न करें। छत्तीसगढ़ सरकार अपने बयानों में हमेशा कहती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। लेकिन महिलाएं काफी परेशान हैं। 10 हजार की नौकरी में अपना जीवन बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पा रहे हैं।

सुकमा में एनएचएम भर्ती की शॉर्टलिस्टिंग पर बवाल

एक पद पर 10 की जगह सिर्फ 5 अभ्यर्थियों को मौका देने का आरोप है.

सुकमा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सुकमा जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (एनएचएम) सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए अपनाई गई शॉर्टलिस्टिंग और मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों में नाराजगी सामने आई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर नहीं दिया गया, जबकि दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला। ये भी आरोप लगा है कि एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग के बावजूद महज पांच अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किए जाने का उल्लेख था, लेकिन लिखित परीक्षा से पहले ही शैक्षणिक मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध केवल पांच अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया। अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया है कि जब अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की गई थी, तो संख्या सीमित रखने का आधार क्या था? शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समान शैक्षणिक प्रतिशत होने के बावजूद कुछ स्थानीय अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं मिली, जबकि बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट निर्धारण के मानकों को लेकर संदेह पैदा हुआ है। अभ्यर्थियों ने प्रशासन से चयन सूची और शॉर्टलिस्टिंग के आधार की जांच कराने की मांग की है। बस्तरिया राज मोर्चा के जिला सचिव रामा सोढ़ी ने स्थानीय युवाओं के पक्ष में आवाज उठाते हुए कहा कि सुकमा एक पिछड़ा एवं अनुसूचित क्षेत्र है, जहां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां बनी हुई हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी सीमित संसाधनों, अभावों और कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में उनकी तुलना बेहतर शैक्षणिक संसाधनों और सुविधाओं के बीच पढ़ाई करने वाले बाहरी अभ्यर्थियों से करना उचित नहीं है। बस्तरिया राज मोर्चा के जिला सचिव ने कहा कि सरकारी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए नियमानुसार उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जिले के शिक्षित युवक-युवतियों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिल सके। इससे न केवल स्थानीय बेरोजगारों को राहत मिलेगी, बल्कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।



लोगों की सेहत से खिलवाड़: दीपावली पर मिठाइयां खा गए बस्तरवासी, अब आएगी शुद्धता की रिपोर्ट

जगदलपुर। दीपावली पर आपने भी मिठाइयां खरीदी होंगी। रंग, स्वाद और सजावट देखकर अपनों का मुंह मीठा भी कराया होगा, लेकिन जरा ठहरिए! जिन मिठाइयों की शुद्धता जांचने के लिए खाद्य विभाग ने दीपावली से पहले सैंपल लिए थे, उनकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। यानी मिठाइयां बिक गईं, लोग खा गए और त्योहार भी बीत गया, लेकिन विभाग अभी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर उन्हीं मिठाइयों में मिलावट या गुणवत्ता की गड़बड़ी निकली तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

दरअसल बस्तर में खाद्य पदार्थों की जांच व्यवस्था की हकीकत कुछ ऐसी है कि विभाग नमूने तो यहां से एकत्र करता है, लेकिन जांच के लिए उन्हें करीब 300 किलोमीटर दूर रायपुर भेजना पड़ता है। जगदलपुर में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए स्थानीय लैब की व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह कि जब तक रिपोर्ट आती है, तब तक संदिग्ध खाद्य सामग्री बाजार से निकलकर लोगों की थाली और पेट तक पहुंच चुकी होती है। खुद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की अधिकारी पूनम कुंजाम के मुताबिक, सितंबर में 30 अक्टूबर में 36 और नवंबर में दीपावली के दौरान 37 नमूने एकत्र कर जांच के लिए रायपुर भेजे गए हैं, लेकिन दीपावली के दौरान लिए गए नमूनों की रिपोर्ट अब तक अप्राप्त है।अब विभाग की इस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने का उद्देश्य क्या सिर्फ सैंपल लेना और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करना है? अगर दीपावली के बाद रिपोर्ट में मिठाइयों के नमूने अमानक पाए जाते हैं, तो क्या विभाग उन लोगों की सेहत की जिम्मेदारी लेगा, जो त्योहार के दौरान इन्हें खा चुके हैं?त्योहारों पर मिलावट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे में जांच की रफ्तार भी उतनी ही तेज होनी चाहिए, लेकिन बस्तर में न अपनी जांच प्रयोगशाला है और न ही तत्काल जांच की पर्याप्त व्यवस्था। सवाल सिर्फ मिठाइयों का नहीं, बल्कि दूध, पनीर, घी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले तमाम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का है।



छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एसएसबी की पहल से 49 युवाओं को इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण

कांकेर। उब कांकेर जिले में ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में एसएसबी की 33 वीं वाहिनी ने ग्राम केवटी में एक माह का इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जिसमें 49 युवाओं को बिजली से जुड़े तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण पूरा होने पर आयोजित समापन समारोह में सभी युवाओं को प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रिशियन टूल किट भी दी गई, ताकि वे प्रशिक्षण के बाद अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। ग्राम केवटी में आयोजित एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईटीआई भानुप्रतापपुर के प्राध्यापकों ने 49 युवाओं को इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायरिंग और विद्युत उपकरणों की मरम्मत से जुड़ा तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। आशा है कि एसएसबी कैंप सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाएगी। हमारे लिए बहुत लाभदायक है।

अम्बिकापुर में मारपीट व छेड़छाड़ के 4 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर में महिला और उसकी भांजी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी के विरुद्ध पहले से ही अंबिकापुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संगठित अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 भी जोड़ी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 24 अक्टूबर 2026 की दोपहर करीब 3.30 बजे की है। प्रार्थिया ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्य आरोपी के घर के पास उसकी भांजी से कुछ आरोपियों ने पूछताछ करते हुए विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने कथित रूप से एकजुट होकर प्रार्थिया और उसकी भांजी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं। शिकायत में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया।

कलेक्टर ने पकड़े 595 क्विंटल धान से लदे दो ट्रक

राजनांदगांव. धान के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर ने पाटेकोरा बैरियर का निरीक्षण किया, जहां अवैध रूप से धान का परिवहन कर रहे दो ट्रक पकड़े गए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, एसडीएम और खाद्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले ट्रक से 742 बोरे (306 क्विंटल) और उसी स्थान पर पकड़े गए दूसरे ट्रक से 289 क्विंटल धान बरामद हुआ। इस प्रकार दोनों वाहनों से कुल लगभग 595 क्विंटल धान जब्त किया गया है। दोनों वाहनों और धान को जब्त कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने बैरियर पर तैनात अमले को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जाए और बिना वैध अनुमति के धान का परिवहन किसी भी स्थिति में न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी सीजन में किसानों के हितों की रक्षा और खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अवैध परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी योजना में उम्र की शर्त बनी रोजगार में बाधा

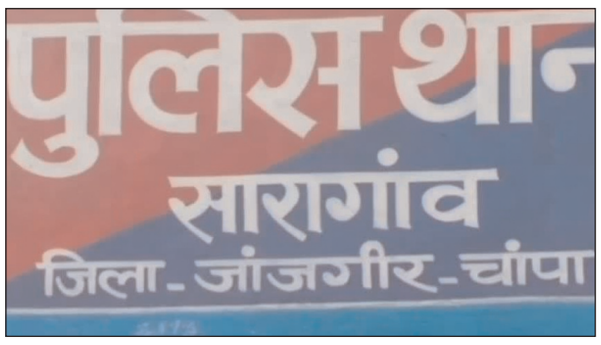
डोंगरगढ़। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन जब योजना की पात्रता शर्तें ही किसी व्यक्ति की आजीविका के रास्ते में बाधा बन जाएं, तो मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला डोंगरगढ़ से सामने आया, जहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन की मांग कर रहे एक साइकिल मैकेनिक को नगर पालिका ने 40 वर्ष से अधिक उम्र होने के आधार पर अपात्र बताया। मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नगर पालिका को याचिकाकर्ता के लिए दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है। दरअसल, डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5, इंदिरा नगर करबला चौक निवासी सतीश बिरहा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वर्ष 2012-13 से स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का व्यवसाय कर अपने परिवार की आजीविका चला रहे थे।

एसईसीएल में तीन माह के निवारक सतर्कता अभियान का समापन

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 17 अगस्त से 16 नवंबर तक संचालित तीन माह के निवारक सतर्कता अभियान के समापन अवसर पर ऑनलाइन ई-आवास पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल आवास आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एसईसीएल की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। पोर्टल का लोकार्पण हरीश दुहन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एसईसीएल द्वारा बिरंची दास, निदेशक (मानव संसाधन); डी. सुनील कुमार, निदेशक (वित्त); हिमांशु जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा नृपेंद्र नाथ, निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे तथा विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। ई-आवास पोर्टल का विकास सतर्कता विभाग की पहल पर मानव संसाधन विभाग एवं सिस्टम विभाग के समन्वित सहयोग से किया गया है।

अवैध शराब बेचने वालों को पैसा लेकर छोड़ा, 4 आरक्षक निलंबित

जांजगीर चांपा। सारागांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोपाल गोंड को शराब के साथ पकड़ा था। इस कार्रवाई में थाना के एक प्रशिक्षु उप निरीक्षक के साथ प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक शामिल थे। लेकिन सभी ने एक राय होकर आरोपी से डेढ़ लाख रुपये लिए और मामूली धारा के तहत कार्रवाई की। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने नगर उप अधीक्षक से जांच कराई। जांच में पैसा लेन देन की बात सही मिली, जिसके बाद एसपी ने सभी 6 जवानों को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुष्पेंद्र साहू के साथ



प्रधान आरक्षक अर्जुन जांगड़े, आरक्षक दीपक सिंह, आरक्षक शंकर जय किशन, आरक्षक सुनील रमना और आरक्षक गोवर्धन टाईगर को निलंबित किया है। जांजगीर सीएसपी योगिताबाली खापर्डे को बिंदु वार जांच के निर्देश दिए है, जिसमे आबकारी एक्ट के आरोपी गोपाल गोंड द्वारा रकम लेनदेन के सम्बन्ध में कथन दर्ज और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करना, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का कथन लेकर उनकी भूमिका और संलिप्तता की जांच करना, और अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध मे जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में भ्रष्टाचार और अवैध रूप से रकम लेन देन के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत अपराध दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी एसपी ने दिए है। सारागाँव थाना में पदस्थ एक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित करने के बाद थाना में एक थाना प्रभारी ही बचा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पांच पुलिस जवानों की पदस्थापना की, जिसमे प्रधान आरक्षक रमेश कुमार त्रिपाठी, आरक्षक पदुम कश्यप, राजेंद्र कुमार साहू, धर्मेन्द्र बंजारे और राजेंद्र कुमार राठौर को रक्षित केंद्र जांजगीर से सारागांव थाना में पदस्थापना दी है।

बलौदाबाजार में दो दिन में 2315 मीट्रिक टन धान की खरीदी

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज होते ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। एक तरफ जिले के 181 उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती रास्तों से आने वाले धान और खरीदी प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए निगरानी का पूरा तंत्र खड़ा किया गया है। जिले की सीमाओं पर 12 अंतर-जिला चेकपोस्ट बनाए गए हैं, वहीं सभी नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई हैं। शुरुआती दो दिनों में जिले में 2,315 मीट्रिक टन धान की खरीदी भी हो चुकी है। जिले में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू हुई। जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मुताबिक पहले दिन 15 नवंबर को जिले के 126 उपार्जन केंद्रों में 411 किसानों के टोकन जारी किए गए थे। इनमें से 353 किसानों ने केंद्रों में पहुंचकर



1,000 मीट्रिक टन धान बेचा।दूसरे दिन यानी 16 नवंबर को 111 उपार्जन केंद्रों में टोकन जारी किए गए। इनमें से 103 केंद्रों में धान खरीदी हुई और इस दिन 1,315 मीट्रिक टन धान की खरीदी दर्ज की गई। इस तरह महज दो दिनों में जिले के उपार्जन केंद्रों से कुल 2,315 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धान खरीदी के दौरान प्रशासन के सामने वास्तविक किसानों से धान खरीद सुनिश्चित करने के साथ-साथ अवैध धान की आवक और संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने की चुनौती भी रहती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 अंतर-जिला चेकपोस्ट गठित किए हैं। इन चेकपोस्टों पर राजस्व, मंडी, सहकारिता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनकी जिम्मेदारी सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और धान से जुड़े संदिग्ध परिवहन पर नजर रखना है। इतना ही नहीं, जिले की सभी नौ तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का भी गठन किया गया है। इन टीमों में राजस्व, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इस व्यवस्था के जरिए तहसील स्तर पर खरीदी प्रक्रिया की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रशासन की रणनीति सिर्फ उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की सीमाओं से लेकर तहसील स्तर तक निगरानी का तंत्र तैयार किया गया है। धान खरीदी के दौरान किसानों को टोकन, खरीदी या उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं से जुड़ी कोई समस्या आती है तो इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम गठित किया है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने की सौजन्य मुलाकात



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मंगलवार को नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर श्री रेड्डी का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने साझा हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री श्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव श्री संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका से रक्तवीर ऋषि ने की सौजन्य भेंट



रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से मंगलवार को रक्तवीर श्री ऋषि अग्रवाल ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को रक्तदान के क्षेत्र में किए जा रहे अपने सेवाभावी कार्यों की जानकारी दी। ऋषि अग्रवाल ने बताया कि वे नियमित रूप से जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत बचत से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी निरंतर सहयोग प्रदान करते हैं। इस वर्ष गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर उन्होंने 54वीं बार रक्तदान किया। राज्यपाल डेका ने ऋषि के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सहायता और रक्तदान के माध्यम से मानव जीवन की रक्षा करना अत्यंत पुनीत कार्य है। उनका यह सेवाभाव समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण है।

गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे अमित जोगी राजेश मूणत ने दर्ज कराई थी एफआईआर



रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज अपनी गिरफ्तारी देने रायपुर के सिविल लाइन थाना पहुंचे हैं। पुलिस जोगी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि हाल ही में अमित जोगी ने बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त के किरदार को दिखाया था। भाजपा नेता राजेश मूणत सिविल लाइन थाना पहुंचकर आपत्तिजनक वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। मीडिया से चर्चा करते हुए मूणत ने कहा था कि अमित जोगी ने देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में जिस प्रकार से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला है और जिस प्रकार के रोल अदा किए हैं वह निंदनीय है। इसके लिए शब्द नहीं है। राजनीति में सिद्धांतों और विचारों की लड़ाई होती है। अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है।

हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी की प्रयोगिक व प्रायोजन परीक्षा 1 से 20 जनवरी तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2027 के नियमित छात्र/छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य 01.01.2027 से 20.01.2027 के मध्य समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तत्संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य को प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य हेतु निर्देश जारी किये गये है।

तूफान अकवान से दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश संभव



रायपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान अकवान छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बस्तर और आसपास के जिलों में इसका असर अधिक रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरा सिस्टम तेजी से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसके 17 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। तूफान के तट से टकराने के दौरान हवा की सामान्य रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। तेज झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों के बाद प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बारिश का असर सिस्टम की दिशा और तीव्रता पर निर्भर करेगा।

शिक्षा से संवरेंगे बस्तर के बच्चों के सपने, प्रतिभाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर

उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर में शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों का किया भ्रमण, विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद



रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शिक्षा की नई संभावनाओं को साकार करने और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने 16 नवंबर को नारायणपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, भविष्य के सपनों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता की मजबूत आधारशिला है।

मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कुम्हारपारा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों के संबंध में चर्चा की। विद्यार्थियों के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे में अपार प्रतिभा और संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता उन्हें सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की है।

इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने विद्यालय के प्राचार्य से शैक्षणिक व्यवस्थाओं, कक्षाओं की स्थिति, शौचालयों की उपलब्धता और परिसर की स्वच्छता सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक एवं सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण के महत्व को रेखांकित किया।

इसके पश्चात मंत्री श्री वर्मा ने नारायणपुर के बखरूपारा स्थित निरामय आरोग्य संस्थान के बालक एवं बालिका छात्रावास का भ्रमण किया। यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों से आए बच्चों के बीच समय बिताया। बच्चों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनके रहन-सहन, अध्ययन, दैनिक गतिविधियों और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि बस्तर के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और अनुकूल अवसर मिलने पर ये बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के जीवन में नई उम्मीदें जगाती है और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के माध्यम से जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मंत्री श्री वर्मा ने निरामय आरोग्य संस्थान द्वारा बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के ये बच्चे कल अपने परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विधायक सोनी, महापौर मीनल व सभापति राठौड ने दी सौगात

आजाद चौक में नये जीर्णोद्धारित सिटी बस स्टाप लोकार्पित



रायपुर। ब्राम्हणपारा वार्ड कमांक 43 क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर जनहित में जनसुविधा हेतु नाली रोड पुलिया आदि के नवीन विकास कार्यों का लगभग 15 लाख रू. की स्वीकृत लागत से आजाद चौक ब्राम्हणपारा के समीप पहुंचकर विधायक सुनील सोनी ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकांत राठौड की उपस्थिति में श्रीफल फोडकर एवं कुदाल चलाकर भूमिपूजन किया।

सोनी ने नगर निगम जोन 4 अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्षेत्र में अधोसंरचना मद से आजाद चौक गार्डन के पास नाली पुलिया निर्माण कार्य 4 लाख 14 हजार रू. में आजाद चौक गार्डन एवं हनुमान मंदिर के पास रोड पुलिया निर्माण मरम्मत कार्य नाली निर्माण कार्य 7 लाख रू. में ब्राम्हणपारा वार्ड अंतर्गत गौरा गौरी चौरा ढीमर पारा कंकाली तालाब के पास विधायक निधि से 4 लाख की लागत से नये स्वीकृत विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

विधायक सोनी ने आजाद चौक ब्राम्हणपारा में 2 लाख 30 हजार रू. की लागत से नवीन जीर्णोद्धारित स्वरूप में सिटी बस स्टाप का लोकार्पण कर बस यात्रियो एवं नागरिको को शानदार सौगात दी। सोनी ने भूमिपूजन करते हुए नये स्वीकृत विकास कार्यों को तत्काल प्रारंभ करवाकर तय समय सीमा के भीतर सतत मॉनिटरिंग करते हुए उच्च स्तरीय गुणवत्ता सहित प्राथमिकता से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी एवं कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह को निर्देशित किया। ब्राम्हणपारा वार्ड पार्षद अजय साहू ने इसके लिए विधायक सुनील सोनी अैर महापौर श्री मीनल चौबे एवं सभापति श्री सूर्यकांत राठौड को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर नगर निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, जोन 4 जोन अध्यक्ष मुरली शर्मा, ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद अजय साहू, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद प्रेम बिरनानी, सुनील वांदरे, सामाजिक कार्यकर्ता केके अवधिया,संजय सोनी, जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी, कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह के अलावा जोन 4 के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायगढ़ गैंगरेप कांड को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार पर बोला हमला

■ कहा- छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा राज्य



रायपुर। रायगढ़ के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती से मारपीट और दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए।

बता दें कि 14 नवंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने गई थी। इसी दौरान दो युवकों ने युवती के प्रेमी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इसके बाद युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अब भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए।

वहीं धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने पिछले साल की धान खरीदी को लेकर भी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। बघेल ने कहा कि इस मांग को लेकर आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन सरकार ने अब तक मौन साध रखा है।

इसके अलावा आरआई परीक्षा पेपर लीक मामले में नए तथ्यों और गिरफ्तारियों को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी में गड़बड़ी सामने आई है। इन सभी मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह जीरो टॉलरेंस की सरकार है।

इंडिया गठबंधन की ओर से एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार निर्वाचन आयोग से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन आयोग की हठधर्मिता और अहंकार के कारण बातचीत नहीं हो पाई। अब आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आया है कि यह संवैधानिक व्यवस्था का मामला है, लेकिन कई बातें उससे भी छिपाई गई हैं।

नगर निगम चिरमिरी में 9 करोड़ 82 लाख 71 हजार के 89 विकास कार्यों को अनुमति

■ पेयजल पाइपलाइन का होगा विस्तार, बनेंगी सड़कें, नालियां और फुटपाथ

रायपुर। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में 9 करोड़ 82 लाख 71 हजार रुपये के 89 विकास कार्यों को अनुमति दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने 15वें वित्त आयोग के अबंधित अनुदान से इन कार्यों को कराने की अनुमति दी है। इनमें पेयजल पाइपलाइन का विस्तार, सीमेंट-कंक्रीट सड़कों और नालियों का निर्माण, पैदल पथ और मार्ग प्रकाश व्यवस्था के कार्य शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विकास कार्यों की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पेयजल पाइपलाइन के विस्तार से लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी। सड़कें और पैदल पथ बनने से आवागमन आसान होगा और नालियों के निर्माण से जल निकासी बेहतर होगी। इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, नागरिकों को रोजमर्रा में सहूलियत होगी और चिरमिरी शहर का स्वरूप भी निखरेगा।

पेयजल व्यवस्था के तहत वार्ड क्रमांक 8 के कोरिया कॉलरी क्षेत्र में संतोषी माता मंदिर के सामने से काली मंदिर तक मुख्य पाइपलाइन के विस्तार के लिए 49.87 लाख रुपये की अनुमति दी गई है। वार्ड क्रमांक 6 के गंगाधर तिलक वार्ड में विभिन्न स्थानों पर पाइपलाइन विस्तार के लिए 28.60 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 10 के हल्दीबाड़ी में 15 लाख रुपये की अनुमति मिली है।

वार्ड क्रमांक 6 और 8 के बीच सीमेंट-कंक्रीट सड़क और आरसीसी नाली के निर्माण के लिए 47.80 लाख रुपये की अनुमति दी गई है। वार्ड क्रमांक 8 में मुख्य मार्ग से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क निर्माण के लिए 9.86 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 31 के गोदरीपारा में कोठारी मैदान के पास मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए 9.90 लाख रुपये की अनुमति मिली है। बड़ा बाजार क्षेत्र में तालाब तक पैदल पथ और तालाब की सुरक्षा दीवार का निर्माण भी कार्ययोजना में शामिल है। संचालनालय ने नगर निगम को सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक तकनीकी, प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कराने तथा गुणवत्ता के साथ तय समयावधि में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

नक्सलवाद की समाप्ति के बाद तेज हुई विकास की रफ्तार

■ पिछले 3 वर्षों में 174 करोड़ की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण



रायपुर। लोक निर्माण विभाग द्वारा आकांक्षी जिला कांकेर के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने वृहद पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और कांकेर जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है। पिछले तीन वर्षों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच 174 करोड़ रुपए की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद समूचे बस्तर संभाग में सड़कों व पुलों के निर्माण में और तेजी आई है।

कांकेर के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कोयलीबेड़ा से पखांजूर मार्ग पर वालेर नदी पर 20 करोड़ रुपए, मेढ़की नदी पर 12 करोड़ रुपए एवं महला नदी पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पुलों का निर्माण किया गया है। इसी तरह भैंसगांव से आतुरबेड़ा मार्ग पर मेढ़की नदी पर 9 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है। इन पुलों के निर्माण ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आवागमन एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके निर्माण से जिले के लगभग 210 गांवों की 1 लाख 68 हजार आबादी को विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालय से बारहमासी संपर्क की सुविधा मिली है।

नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद कांकेर जिले में वृहद पुल निर्माण कार्यों में तेजी आई है। विगत कुछ महीनों में ही 61 करोड़ रुपए की लागत से 9 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इनमें करेगांव-मंडगांव मार्ग पर 7 करोड़ 46 लाख रुपए, बांसपत्तर-तिरियारपानी मार्ग पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए, टुरी नदी पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए तथा कापसी (पी.वी.-130)-पखांजूर मार्ग में त्रास नाला पर 6 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से जिले के 80 गांवों की लगभग 56 हजार आबादी को वर्षभर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई है। इन पुलों से क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा, व्यापार, उन्नत कृषि, पर्यटन गतिविधियां, सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शासन की योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है।

नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद नारायणपुर माड़ क्षेत्र सहित कांकेर जिले के सुदूर अंचलों में विकास और अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इनमें मरबेड़ा-सितरम मार्ग पर कोटरी नदी में 19 करोड़ रुपए, कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग पर मेढ़की नदी में 10 करोड़ रुपए तथा ताड़ोकी-बैहासाल्हेभाट मार्ग पर मेढ़की नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर-नारायणपुर मार्ग पर बेचाघाट में कोटरी नदी पर 17 करोड़ रुपए की लागत से वृहद पुल का निर्माण तेजी से जारी है। इन पुलों के पूर्ण होने से दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा तथा महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय आवागमन की भी सुविधा मिलेगी।

कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों को मुख्य जिला मार्गों, राज्य मार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने तथा विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालयों से बारहमासी संपर्क सुनिश्चित करने राज्य शासन द्वारा 140 करोड़ रुपए की लागत से 19 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके साथ ही 92 करोड़ रुपए की लागत से 10 नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इन स्वीकृत पुलों में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा नदी में 6 करोड़ रुपए, मरोड़ा-बेलगांव-छोटेबिटिया मार्ग पर बेलगांव नाला में 4 करोड़ रुपए के पुल शामिल है।

कांग्रेस ने केवल एक परिवार की वंदना के कारण स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए आदिवासी नायकों की उपेक्षा की : भाजपा

■ प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने जनजाति गौरव दिवस पर कांग्रेस पर साधा निशाना

रायपुर। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते कहा कि पूरा देश जनजाति गौरव दिवस मना रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कहीं भी आदिवासी समाज को इस दिवस की बधाई नहीं दी।

ठाकुर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का उल्लेख करते हुए कहा कि वे स्वयं भगवान बिरसा मुण्डा की धरती (झारखण्ड) से आते हैं, इसके बावजूद उन्होंने जनजाति समाज को जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं नहीं दीं। श्री ठाकुर ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में आजादी से 100 वर्ष पूर्व से ही आदिवासी समाज के वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिल सका। कांग्रेस ने केवल एक परिवार की वंदना के कारण स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए आदिवासी नायकों की उपेक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति वर्ग के नायकों को सम्मान देने का बीड़ा



उठाया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को %जनजाति गौरव दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा, छत्तीसगढ़ के परलकोट के शहीद गेंद सिंह नायक और शहीद वीर नारायण सिंह सहित सभी आदिवासी बलिदानियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है।

ठाकुर ने कहा कि आदिवासी समाज को मुख्यधारा में आगे लाने और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन, ओड़िशा में मोहनचरण माँझी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समाज का मान बढ़ाया है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 02 रायपुर (छ.ग.)

सूचना

दिनांक 16/11/2026

सूचित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार साहू, पिता स्व. श्री कामता प्रसाद साहू (Employee ID 6619015130) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, निर्माण उपसंभाग क्रमांक 02 रायपुर में नियमित अकुशल श्रमिक के पद पर कार्यरत् है। आप दिनांक 01.10.2017 से आज दिनांक तक अपने कार्य से लगातार अनुपस्थित है। आपको इस कार्यालय के पत्र क्र. 6697/स्था/2017-18 रायपुर, दिनांक 07.09.2017, पत्र क्र. 6572/स्था/2020-21 रायपुर, दिनांक 04.12.2020, पत्र क्र. 1368/स्था/2022-23 रायपुर, दिनांक 16.03.2023, पत्र क्र. 4241/का.भा. दिनांक 20.07.2026 द्वारा कार्य पर उपस्थित होने के लिए लेख किया गया परंतु आपने आज दिनांक तक उक्त पत्रों का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और ना ही आप कार्य पर उपस्थित हुए। आपका उक्त कृत्य कदाचरण के श्रेणी में आता है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको अंतिम अवसर दिया जाता है कि इस प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपने कार्य में उपस्थिति दर्ज करावें। उपस्थित नहीं होने पर आपको कार्य में कोई रूचि नहीं है यह माना जावेगा तथा शासकीय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग
क्र. 02 रायपुर (छ.ग.)

जी-262704540/2

सलाखों के पीछे इमरान और शहबाज के हवाई सपने

दिलीप कुमार पाठक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कभी पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय चेहरा हुआ करते थे और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाक का प्रतिनिधित्व करते थे, आज जेल की तन्हाई में अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं। अदियाला जेल की चारदीवारी से आए उनके संदेश ने पूरे पाकिस्तान को बेनकाब करने के साथ-साथ मानवता को भी झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि जिस तरह के हालात में उन्हें रखा गया है और जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, उससे उनका जिंदा वापस लौट पाना मुश्किल है। पाकिस्तान की राजनीति के इस खौफनाक सच के ठीक उलट, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश और दुनिया को यह सपना दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द ही दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है। हाल ही में पाकिस्तान के मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोल्डमैन सैक्स की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान साल 2075 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन वे इसमें थोड़ा सुधार करना चाहते हैं। मियां शहबाज के मुताबिक, यह चमत्कार 2075 तक नहीं बल्कि साल 2050 से भी पहले हो जाएगा। अब इन दावों की हकीकत की पड़ताल करते हैं तो कुछ और ही सच सामने आता है। 130 अरब डॉलर से ज्यादा के विदेशी कर्ज के बोझ तले दबे और आईएमएफ तथा चीन की बैसाखियों पर टिके रहने वाले जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार हर दूसरे दिन सुर्खियों में रहता हो, वहां 2050 तक दुनिया की शीर्ष छह अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखना सिर्फ एक छलावा ही है। जिस मुल्क में रोजमर्रा की बुनियादी चीजें दुर्लभ हो चुकी हों और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी हो, वहां इस तरह के हवाई किले बनाने पर खुद देश-दुनिया के विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या तब तक पाकिस्तान नाम का वजूद बचेगा भी या नहीं? यह भी किसी से छिपा नहीं है कि पड़ोसी देश की इस खस्ताहाली के पीछे असल खेल किसका है। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट दिग्गजों, बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों ने मिलकर इस पूरी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है। पाकिस्तान की जनता महंगाई की चक्की में पिसती है, और हुक्मरान लूट का काला धन ठिकाने लगाकर लंदन और दुबई में अपने बच्चों के नाम पर आलीशान फ्लैट और बंगले खरीद चुके हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन वहाँ की अवाम का सब्र टूटेगा, ये सबसे पहले देश छोड़कर भाग खड़े होंगे। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में वहां की युवा पीढ़ी के सामने सेना और हुकूमत का गढ़ा हुआ पुराना प्रोपोगंडा बेनकाब हो चुका है। आज पाकिस्तान का युवा न्यूट्रल इतिहास खंगाल रहा है और यह सच जान रहा है कि कैसे चंद लोगों ने अपनी तिजोरियों के लिए पूरे देश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान के साथ जिस तरह का क्रूरता की जा रही है और मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखा जा रहा है, वह पाकिस्तान की अंदरूनी सड़न को पूरी तरह उजागर करता है। अगर जेल के भीतर कुप्रबंध या प्रताड़ना के चलते इमरान खान को कुछ हो गया, तो यह पाकिस्तान की जर्जर होती व्यवस्था और तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। फिर दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था बनने के हवाई दावे तो दूर, पाकिस्तान खुद ही बिखर जाएगा। जनता के भीतर सुलगती यह विद्रोही आग एक न एक दिन फटेगी जरूर, और तब इन सत्ता के ठेकेदारों का क्या होगा, यह वक्त तय करेगा।

वंतारा से गौ सेवा तक अनंत अंबानी की मानवीय सेवा यात्रा

ललित गर्ग

आज जब दुनिया व्यापार को प्राय: लाभ, प्रतिस्पर्धा, विस्तार और बाजार की भाषा में परिभाषित करती है, तब अनंत अंबानी का व्यक्तित्व इस स्थापित धारणा के सामने एक अलग प्रश्न खड़ा करता है-क्या बड़ी आर्थिक सफलता के साथ बड़ी मानवीय संवेदना भी संभव है? क्या अरबों-खरबों की व्यावसायिक दुनिया में करुणा, जीवदया, सेवा और पर्यावरण-संरक्षण केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के औपचारिक शब्द रहेंगे या वे जीवन-दर्शन का हिस्सा बन सकते हैं? अनंत अंबानी की गतिविधियाँ इस प्रश्न का एक सकारात्मक उत्तर देती दिखाई देती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े अनंत अंबानी आज केवल व्यापारिक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि पशु कल्याण, जीवदया और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उनकी सबसे चर्चित पहल 'वंतारा'-स्टार ऑफ द फॉरेस्ट है, जो गुजरात के जामनगर में लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्र में विकसित पशु बचाव, उपचार, पुनर्वास और संरक्षण का विशाल केंद्र है। हाल ही में केरल की 18 महीने की बीमार और घायल नन्हीं हथिनी 'माया' की जान बचाने के लिए उसे एयरलिफ्ट कराकर जामनगर स्थित अपने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वंतारा में भर्ती कराया है। रिलायंस फाउंडेशन के अनुसार वंतारा में 1.5 लाख से अधिक पशुओं और 2,000 से अधिक प्रजातियों की देखभाल की जा रही है तथा इसके लिए हजारों विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और देखभालकर्ताओं की टीम कार्यरत है।

लेकिन अनंत अंबानी की चर्चा केवल वंतारा तक सीमित नहीं है। हाल में उनके गौसेवा संबंधी वक्तव्य ने देश का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। एक वायरल वीडियो में उन्होंने लगभग नौ लाख गायों की देखभाल से जुड़े होने की बात कही, जिनमें करीब सात लाख गायें ऐसी बताई गईं जो दूध नहीं देतीं या आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। उन्होंने घायल एवं संकटग्रस्त गायों के बचाव के लिए लगभग 100 एम्बुलेंस और आठ राज्यों में सक्रिय बचाव-व्यवस्था का भी उल्लेख किया। यहीं अनंत की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। जो पशु दूध नहीं देता, जिसकी आर्थिक उपयोगिता समाप्त हो गई है, क्या उसका जीवन भी कम मूल्यवान हो जाता है? बाजार की सामान्य मानसिकता शायद इस प्रश्न का उत्तर उपयोगिता से देगी, लेकिन जीवदया की भारतीय परंपरा इसका उत्तर अस्तित्व के सम्मान से देती है।



अनंत अंबानी की गौसेवा की चर्चा इसी बिंदु पर एक व्यापक सामाजिक विमर्श को जन्म देती है-किसी जीव का मूल्य उसकी उत्पादकता से नहीं, उसके जीवन से तय होना चाहिए। यह विचार आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यापार की सफलता का अर्थ केवल अधिक उत्पादन और अधिक लाभ नहीं होना चाहिए, उसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ना चाहिए कि उस सफलता से समाज, प्रकृति और जीव-जगत को क्या मिला। यदि पूंजी संवेदना से जुड़ती है, तकनीक करुणा के साथ चलती है और उद्योग पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनता है, तो व्यापार केवल आर्थिक संस्था नहीं रहता, वह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। अनंत अंबानी की दिनचर्या से जुड़ी बातें भी इसी संवेदनशीलता की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने बताया है कि घर से निकलने से पहले वे गायों की मालिश करते हैं और उनके घर में छह गायें हैं, जिन्हें वे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराते हैं। यह बात प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बड़े उद्योग-घराने की सुविधाओं में रहने वाला कोई युवा यदि अपने दैनिक जीवन में किसी पशु के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव को स्थान देता है, तो वह सेवा को केवल दान की गतिविधि नहीं रहने देता, उसे व्यक्तिगत संस्कार में बदल देता है।

वंतारा इस व्यक्तिगत संवेदना का संस्थागत और वैज्ञानिक विस्तार दिखाई देता है। यहां पशुओं के उपचार, पुनर्वास और संरक्षण के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ विकसित की गई हैं। रिलायंस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वंतारा में विशेषीकृत वन्यजीव अस्पताल, पशु चिकित्सा सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ, पोषण केंद्र और संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी संचालित हैं। यानी यह केवल 'पशुओं को बचाने' की भावना नहीं है, इसके साथ विज्ञान, चिकित्सा, जैव-विविधता और दीर्घकालीन संरक्षण को जोड़ा गया है। यही वह जगह है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति कहती है-'अहिंसा परमो धर्म:', जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि जैव-विविधता का संरक्षण मानव सभ्यता के भविष्य के लिए आवश्यक है। वंतारा इन दोनों विचारों को एक साझा धरातल देता है।

इसी सोच का विस्तार अक्टूबर 2026 में आरंभ हुई 'चैंपियंस ऑफ केयर' पहल में भी दिखाई देता है। विश्व पशु दिवस के अवसर पर शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत 50 से अधिक पशु कल्याण संगठनों को साथ लाने का प्रयास किया गया है, जो सामुदायिक कुत्तों, बिल्लियों, मवेशियों और अन्य पशुओं के लिए चिकित्सा, बचाव और दीर्घकालीन देखभाल का काम करते हैं। इसका लक्ष्य पशु कल्याण को केवल एक बड़े केंद्र तक सीमित रखने के बजाय देशभर के जमीनी संगठनों तक सहायता पहुँचाना है। यहाँ अनंत अंबानी के दृष्टिकोण की एक और विशेषता दिखाई देती है-केंद्रीकरण से सहयोग की ओर बढ़ना। यदि देश में पहले से काम कर रहे छोटे-छोटे पशु कल्याण संगठन संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें खत्म करने के बजाय मजबूत करना अधिक प्रभावी सामाजिक मॉडल है। यही मॉडल भविष्य में पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क का आधार बन सकता है।

अनंत की सोच को केवल भावुकता कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो इतने बड़े पशु-कल्याण अभियानों की वास्तविक कसौटी पारदर्शिता, वैज्ञानिक मानक, पशु-अधिकार, दीर्घकालीन पुनर्वास, जैव-सुरक्षा और स्वतंत्र मूल्यांकन होगी। वंतारा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रश्न और बहसें भी हुई हैं, इसलिए ऐसे विशाल संस्थानों के लिए पारदर्शिता और प्रमाण-आधारित संचालन उतना ही आवश्यक है जितना करुणा। यही आलोचनात्मक कसौटी किसी भी बड़े परोपकारी प्रयास को अधिक विश्वसनीय बनाती है। करुणा भाव है, लेकिन करुणा का स्थायी प्रभाव व्यवस्था से पैदा होता है। इसीलिए अनंत अंबानी के बारे में यह कहना अधिक उचित होगा कि वे व्यापार की पुरानी परिभाषा को अस्वीकार करने के बजाय उसमें एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि हर बड़ा व्यापार ईमानदारी और नैतिकता से ही चलता है, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनका सार्वजनिक आचरण यह संदेश देता है कि व्यावसायिक महत्वाकांक्षा और मानवीय संवेदना एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

अनंत अंबानी के व्यक्तित्व का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम उनके हालिया जियो संबोधन में सामने आया। 28 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ऐतिहासिक सूचीबद्धता के अवसर पर उन्होंने सफलता का श्रेय केवल परिवार या प्रबंधन को नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों को दिया। उन्होंने व्यापार को पूजा और शेयर बाजार की घंटी को मंदिर की घंटी से जोड़ते हुए कहा कि पूजा का प्रसाद बांटा जाता है और 卐आज जियो भारत के साथ साझा किया गया है।卐 उनके संबोधन के दौरान मुकेश अंबानी भावुक होकर आँसू पोंछते दिखाई दिए। यह प्रसंग महज पारिवारिक भावुकता नहीं था। इसमें व्यापार के अर्थ की एक नई व्याख्या छिपी थी-व्यापार केवल मालिक का नहीं, उससे जुड़े करोड़ों लोगों का भी होता है। जियो की सफलता को उन्होंने कर्मचारियों, तकनीशियनों, सेवा-कर्मियों, खुदरा भागीदारों और सामान्य भारतीयों की भागीदारी से जोड़ा। यही दृष्टि व्यापार को 'मैं' से 'हम' की ओर ले जाती है।

एचएफसीएल के अध्यक्ष एवं दूरसंचार क्षेत्र के वरिष्ठ उद्योगपति महेंद्र नाहटा लंबे समय से जियो की यात्रा से जुड़े रहे हैं और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के निदेशक मंडल में भी रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से अनंत अंबानी की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह मानी जा सकती है कि उन्होंने तकनीक और व्यवसाय की आधुनिक दुनिया को सेवा, संस्कार और संवेदना से जोड़ने की कोशिश की है। जियो की ऐतिहासिक सफलता के अवसर पर अनंत के भावपूर्ण संबोधन में नाहटा ने भी भारतीय आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और मानवीय संवेदना के संगम की झलक देखी-ऐसा विचार उनके हालिया लेख में व्यक्त हुआ है। अनंत ने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है-क्या कारोबार का अंतिम लक्ष्य केवल लाभ है, या लाभ के साथ लोकमंगल भी? यदि व्यापार में तकनीक हो, तो वह विकास बनता है। उसमें पूंजी हो, तो वह विस्तार बनता है। लेकिन उसमें करुणा जुड़ जाए, तो वही व्यापार सेवा का माध्यम बन सकता है। अनंत अंबानी की गौसेवा, वंतारा और सामुदायिक पशु कल्याण की पहलें इसी संभावित परिवर्तन की कहानी कहती हैं।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

हर्ष की बात है कि यह ग्रन्थ मनोरथनन्दिकृत वृत्ति सहित श्री राहुल साङ्कृत्यायन द्वारा सम्पादित होकर बिहार रिसर्च सोसायटी के जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। साथ ही प्रमाणवार्तिक के एक भाग पर प्रज्ञाकर गुप्त की वार्त्तिकालङ्कार नामक टीका भी प्रकाशित हो चुकी है।

धर्म-कीर्ति का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हेतुबिन्दुविनिश्चय है। इसमें प्रमाण-वार्त्तिक के विषय को संक्षिप्त रूप में दिया है। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जो कि दिनाग सम्प्रदाय को समझने में इस समय हमारा सबसे बड़ा सहायक है, धर्मकीर्त्ति का न्यायबिन्दु है। यही अकेला ग्रन्थ है जिसका ठीक-ठीक सम्पादन होकर अनुवाद भी हो चुका है। न्यायबिन्दु धर्मोत्तर की टीका सहित बहुत पहिले पीटर्सन द्वारा सम्पादित होकर

कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ था। परन्तु हर्ष की बात है कि श्चेरबात्स्की द्वारा सम्पादित, धर्मोत्तर टीका सहित न्यायबिन्दु का एक विशेष संस्करण रूस में छप चुका है, और Buddhist Logic की द्वितीय जिल्द में स्वेरबात्स्की द्वारा न्यायबिन्दु का अंग्रेजी का अनुवाद विस्तृत और अर्थ प्रकाश करने वाली टिप्पणियों सहित छप चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि न्यायबिन्दु का रूसी संस्करण और अनुवाद दोनों ही इस समय भारत में अप्राप्य हैं और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रमुख पुस्तकालयों में भी वे विद्यमान नहीं। धर्मोत्तर के सिवाय न्यायबिन्दु का टीकाकार विनीतदेव भी था, उसका ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका है।

जम्बूद्वीप के वै रत्न : धर्मकीर्त्ति बौद्ध दर्शन का अन्तिम चमकता हुआ तारा है। धर्मकीत्ति (7वीं सदी का मध्यकाल) के समय में ही बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो रहा था।

क्रमश: ...

पद्मावती के साथ मायके में हुआ छल, बच्चे के जन्म पर नामकरण कंस हुआ

आशुतोष गर्ग

मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनका विवाह विदर्भराज सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती से हुआ था। उग्रसेन अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उसके बिना भोजन तक नहीं करते थे। दोनों का दांपत्य जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीत रहा था। कुछ समय बाद पद्मावती के पिता सत्यकेतु को अपनी पुत्री की याद आई। उनकी माता भी उन्हें देखने के लिए व्याकुल थीं। उन्होंने दूत भेजकर उग्रसेन से आग्रह किया कि पद्मावती को कुछ समय के लिए मायके भेज दें। उग्रसेन ने स्नेहपूर्वक उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और पद्मावती विदर्भ चली गईं।

एक दिन अपने मायके में पद्मावती अपनी सखियों के साथ किसी उपवन में घूम रही थीं। वहीं एक सुंदर सरोवर था। पद्मावती अपनी सखियों के साथ उसमें जलक्रीड़ा करने लगीं। उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि पद्मावती पर पड़ी, तो वह मोहित हो गया और उसके मन में कुटिल विचार उत्पन्न होने लगे।



उसे ज्ञात था कि पद्मावती पतिव्रता हैं, इसलिए सामान्य रूप से उन्हें पाना असंभव था। तब गोभिल ने छल किया और मायाशक्ति से उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। फिर, उसने मधुर संगीत में गाना शुरू किया। पद्मावती ने जब वह स्वर सुना, तो उन्हें लगा कि शायद उग्रसेन वहां आए हैं। वह अपनी सखियों के साथ उसके पास पहुंचीं। गोभिल ने उग्रसेन के स्वर में उसे पुकारा, 'प्रिये! तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हारे वियोग में जीवन मेरे लिए असह्य हो गया है।' पद्मावती उसके छल को पहचान न सकीं। गोभिल उसे एकांत में ले गया और फिर उसने पद्मावती के साथ समागम किया। उस बीच पद्मावती ने ध्यान से देखा कि गोभिल के शरीर में वह विशेष चिह्न नहीं था, जो उसके वास्तविक पति उग्रसेन के शरीर में था। यह देखकर वह क्रोधित होकर बोलीं, 'तुमने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे पातिव्रत्य को नष्ट किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप दूंगी।' गोभिल ने पद्मावती पर ही दोष लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा, 'यदि पतिव्रता हो, तो पति को छोड़कर यहां क्यों आई हो? शृंगार, आभूषण व सुंदर रूप धारण करके क्यों घूम रही हो?

उसने आगे कहा, 'दंड देकर मैं तुम्हें सीधी राह पर ले आया हूं। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती।' गोभिल ने पद्मावती को अपराधिनी सिद्ध करने की कोशिश की।

पद्मावती ने उत्तर दिया, 'मेरे पिता ने स्नेह के कारण मुझे कुछ समय के लिए मायके बुलाया है। मैं यहां भी अपने पति का स्मरण करती हूं। तुमने उनका रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है। अपराधी तुम हो, मैं नहीं!' परंतु, गोभिल ने कहा, 'तुम्हारे मन में मायके आने की इच्छा उत्पन्न हुई, उसी क्षण तुम्हारा मन पति के चिंतन से हट गया था।' उसके तर्क सुनकर पद्मावती का दुख और बढ़ गया। अंतत: गोभिल ने कहा, 'तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, जो तीनों लोकों के लिए भय का कारण बनेगा।' यह कहकर वह चला गया। पद्मावती फूट-फूटकर रोने लगीं। उन्होंने सखियों को अपने साथ हुए छल की घटना सुनाई। उसकी सखियों ने यह सारी बात पद्मावती के माता-पिता को बताई तो, वे बहुत दुखी हुए।

पाकिस्तान आर्मी में बलूचों ने लगाई बड़ी सेंध

नीरज कुमार दुबे

पाकिस्तान की सेना जिस बलूच विद्रोह को अपनी ताकत के दम पर कुचलने में जुटी है, अब उसी विद्रोह की कमान उसके अपने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में आ गई है। हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तानी सेना के पूर्व कैप्टन रहमान गुल को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। कभी पाकिस्तान की वर्दी पहनकर सैन्य अभियानों का हिस्सा रहे रहमान गुल अब उसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। जिस सेना की ताकत, कार्यप्रणाली और सैन्य रणनीति को रहमान गुल करीब से समझते हैं, अब वही अनुभव बलूच विद्रोह के नेतृत्व में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और संगठनात्मक पूंजी बन सकता है।

यह नियुक्ति इसलिए भी असाधारण है क्योंकि रहमान गुल केवल पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन चुके अधिकारी नहीं हैं, बल्कि वह बीएलए की ताकतवर मजीद ब्रिगेड का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनके पास पाकिस्तानी सेना के कामकाज का अनुभव है और बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठन के भीतर वर्षों का कमांड अनुभव भी। पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम निश्चित रूप से रणनीतिक चिंता बढ़ाने वाला है।

हम आपको बता दें कि रहमान गुल ने वर्ष 2002 में पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी के 109वें लॉन्ग कोर्स के माध्यम से सेना में प्रवेश किया था। वह 19 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर रहे। उनकी तैनाती उत्तर वजीरिस्तान, दक्षिण वजीरिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली सेक्टर में भी रही। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाए, उनमें भी रहमान गुल की भूमिका रही थी। करीब आठ वर्ष सेना में रहने के बाद उन्होंने 2010 में सैन्य सेवा छोड़ दी और बीएलए से जुड़ गए। इसके बाद संगठन में उनकी



हैसियत लगातार बढ़ती गई। वह फील्ड कमांडर से लेकर मजीद ब्रिगेड के प्रमुख और वरिष्ठ कमांड काउंसिल के सदस्य तक पहुंचे। अब उन्हें संगठन की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

देखा जाये तो पाकिस्तानी सेना की कार्यप्रणाली, उसकी कमान संरचना, सैन्य रणनीति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की बारीकियों से परिचित रहमान गुल अब उसी सेना के सबसे बड़े विद्रोही संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में आज भी उनके संपर्क सूत्र मौजूद हैं और उनसे जुड़े कुछ लोग लगातार उन्हें सेना की गतिविधियों और अंदरूनी घटनाक्रमों की जानकारी पहुंचा रहे हैं। यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए चुनौती और गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसे अब केवल एक पूर्व सैन्य अधिकारी के अनुभव का ही सामना नहीं करना होगा, बल्कि सेना के भीतर मौजूद पुराने संपर्कों से सूचनाएं बाहर पहुंचने की आशंका से भी जूझना पड़ सकता है। जिस सैन्य तंत्र की गोपनीयता और रणनीतिक बढ़त के भरोसे पाकिस्तान बलूच विद्रोह को दबाना चाहता है, उसी तंत्र से जुड़ा एक पूर्व अधिकारी अब उसके खिलाफ खड़ा है।

हम आपको यह भी बता दें कि रहमान गुल की नियुक्ति का दूसरा बड़ा पहलू बीएलए की संगठनात्मक क्षमता है। वह पहले ही मजीद ब्रिगेड जैसी प्रभावशाली इकाई का नेतृत्व कर चुके हैं। इस ब्रिगेड का नाम पाकिस्तान में कई बड़े हमलों और चीनी हितों को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों से जुड़ा रहा है। ऐसे में उनका कमांडर-इन-चीफ बनना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन के सैन्य अनुभव और सर्वोच्च नेतृत्व के बीच पहले से मौजूद संबंध को और मजबूत करना है।

देखा जाये तो बीएलए को अब ऐसा प्रमुख मिला है जो पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक सैन्य सोच और विद्रोही संगठन की वास्तविकताओं, दोनों से परिचित है। वह जानता है कि किसी नियमित सेना की ताकत कहां होती है और लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह में संगठन के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं। इससे बीएलए को अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद मिल सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रहमान गुल का सेना से विद्रोही संगठन तक पहुंचना पाकिस्तान के उस दावे को भी चुनौती देता है, जिसमें बलूचिस्तान के संघर्ष को केवल बाहरी ताकतों की साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। जब उसी सेना का पूर्व अधिकारी बलूच आंदोलन का सर्वोच्च नेतृत्व संभालता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पाकिस्तान की अपनी सैन्य व्यवस्था के भीतर ऐसा असंतोष पैदा क्यों हो रहा है?

हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, गैस और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिहाज से इसका महत्व बहुत बड़ा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन की निवेश परियोजनाओं तक पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से जुड़ा है। लेकिन जिस क्षेत्र को पाकिस्तान अपनी आर्थिक तरक्की का प्रवेश द्वार बनाना चाहता है, वही उसके लिए लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बीएलए की गतिविधियां पाकिस्तान की सेना और सरकार को लगातार चुनौती देती रही हैं। अब रहमान गुल की नियुक्ति इस संघर्ष को एक नया राजनीतिक और प्रतीकात्मक आयाम देती है।

इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बीएलए ने अपने पूर्व प्रमुख बशीर जेब बलूच के हटने के बाद वरिष्ठ कमांड काउंसिल के माध्यम से नेतृत्व परिवर्तन किया। संगठन ने दावा किया कि यह फैसला आंतरिक सहमति से हुआ और इससे उसके कामकाज में कोई रुकावट नहीं आई। यदि यह संगठनात्मक निरंतरता बनी रहती है तो पाकिस्तान के लिए विद्रोही नेतृत्व को कमजोर करने की चुनौती और कठिन हो सकती है। दूसरी ओर, रहमान गुल की नियुक्ति बलूच आंदोलन के लिए मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक बढ़त है। यह संदेश पाकिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह जाएगा कि बलूचिस्तान का संघर्ष केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिन्होंने कभी सैन्य या सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं देखा। उस व्यवस्था के भीतर काम कर चुका व्यक्ति भी अब उसके खिलाफ खड़ा है।

एक और फायदा नेतृत्व के स्तर पर है। बीएलए को ऐसा कमांडर मिला है जिसके पास सेना और विद्रोही संगठन, दोनों का अनुभव है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भी बलूचों को फायदा मिलने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान में मानवाधिकारों, जबरन गुमशुदगी और राजनीतिक असंतोष के आरोपों का सामना करता रहा है। ऐसे में सेना के पूर्व अधिकारी का विद्रोही संगठन का नेतृत्व करना इस संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में और प्रमुखता दे सकता है। हालांकि, अभी असली परीक्षा यह होगी कि नया नेतृत्व बलूच संगठन की एकजुटता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस हद तक मजबूत कर पाता है।

बहरहाल, पाकिस्तान के लिए असली संकट बीएलए की कमान एक पूर्व सैन्य अधिकारी के हाथों में जाना भर नहीं है, बल्कि यह है कि अब उसके खिलाफ उठ रही बगावत का नेतृत्व वही व्यक्ति कर रहा है, जिसने कभी उसकी सेना की वर्दी पहनकर उसी सैन्य तंत्र के भीतर काम किया है।

आज का इतिहास

1727 महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। बंगाल के विद्यासागर चक्रवर्ती इस शहर के वास्तुकार थे।
1738 फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
1772 पेशवा माधव राव प्रथम का निधन और उनके स्थान पर उनके छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली।
1833 हॉलैंड और बेल्जियम के बीच जोनहोवेन संधि पर हस्ताक्षर हुआ।
1909 अमेरिका ने निकारागुआ पर हमला किया।
1918 उत्तरपूर्वी यूरोपीय देश लातविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की।
1922 तुर्की के युवराज अब्दुल मजीद द्वितीय को खलीफा चुन लिया गया।
1928 में पहली बार वॉल्ट डिजनी कंपनी का मैस्कॉट स्टीमबोट विली नजर आया। जिसका नाम मिकी माउस पड़ गया।
1948 बिहार की राजधानी पटना के निकट स्टीमर 'नारायणी' के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच सौ लोग डूबे।
1951 ब्रिटिश सेना ने मिस्र के इस्मालिया क्षेत्र पर कब्जा किया।
1956 मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की
1959 विमानवाहक पोत एचएमएस हर्मुज़ को ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल किया गया, जिसे 1984 में सेवामुक्त करके भारत को बेच दिया गया।1987 में इसे आईएनएस विराट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जहां इसने 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं दीं।
1963 अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लाई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड था।
1976 स्पेन की संसद ने 37 बरस की तानाशाही के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
1978 दक्षिण अफ्रीका के गुयाना में एक धार्मिक समुदाय पीपुल्स टैंपल क्रिश्चियन चर्च के सदस्यों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। शीतल पेय में जहर डालकर पीने से 900 से ज्यादा लोगों की मौत। इनमें 276 बच्चे थे।
1994 फ़लस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता प्रदान की।
2008 केन्द्र सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में 50,000 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया।
2013 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा।
2017 भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता।

सिर्फ राजधानी नहीं, समृद्धि का नया रास्ता है अमरावती मॉडल

शेखर गुप्ता

इस सप्ताह का यह स्तंभ अमरावती से लिखा गया है। अमरावती यानी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जिसे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कृष्णा नदी के दूसरे तट पर विजयवाड़ा के समक्ष बसा रहे हैं। यद्यपि यह लेख अमरावती के बारे में नहीं बल्कि एक विचार को लेकर है। यह भारतीय राजनीति में एक नया विचार है। खासकर ऐसे युग में जब कोई राजनेता नहीं चाहता है कि वह कोई ऐसी चीज बनाए जिसे चार साल में पूरा नहीं किया जा सके। इसलिए क्योंकि कार्यकाल का पांचवां साल तो वैसे भी चुनावी तैयारियों के लिए रहता है।

एक राजधानी बनाने में अधिक समय लगता है। एक कार्यकाल शायद मतदाताओं को इसे एक सफलता के रूप में दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हो। और अगर सत्ता छिन गई तब क्या होगा? नायडू के साथ 2019 में यही तो हुआ। उस समय तक वह बस जमीन का एक टुकड़ा ही जुटा पाए थे। उनके बाद आए वाई एस जगन मोहन रेड्डी और उनके दल वाईएसआरसीपी (युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी) ने इस परियोजना को यह कहकर नकार दिया कि यह केवल नायडू की जाति के लोगों के लिए लाभप्रद है क्योंकि परियोजना के लिए ली गई अधिकांश जमीन उनकी ही कम्मा जाति के किसानों से ली गई थी।

रेड्डी ने परियोजना को निरस्त कर दिया, जमीन देने वाले किसानों को भुगतान रोक दिया और यह घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां होंगी- विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। विकेंद्रीकरण का विचार दिलचस्प हो सकता है लेकिन इस प्रकार नहीं। आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य है और विशाखापत्तनम और कुर्नूल के बीच 700 किलोमीटर की दूरी है जबकि अमरावती ठीक बीच में है। इसे तुगलकी फरमान कहा जा सकता है और मैंने ऐसा किया भी। रेड्डी और उनके दल के नेता विनम्र बने रहे लेकिन उनके परिवार के मालिकाने वाले समाचार पत्र साक्षी ने मेरा स्तंभ नहीं छापा। तेलुगू में मेरे स्तंभ को छापने का अधिकार उन्हीं के पास है।

नायडू की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने इस विचार को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने इसे फिर से साकार करने का वादा किया था और अब वे इसे बेहद तेज गति से आकार दे रहे हैं। गति इतनी तेज है कि भविष्य में यदि सत्ता परिवर्तन भी होता है तो इस परियोजना को पलटने के लिए शायद ही कुछ बाकी रह जाएगा। नई राजधानी इतनी तेजी से आकार ले रही है कि चुनावी नतीजे भी इतनी जल्दी नहीं बदलते। इतनी महत्त्वाकांक्षी, विशाल और खर्चीली परियोजना के प्रति यह दृढ़ता ही इसे असाधारण बनाती है। ऐसी नई जीवंत नगरी बसाने का विचार, जिसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, हाईटेक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ एक आत्मा भी हो, हमारे लिए नया है।

हमने जरूरत के मुताबिक सरकारी बस्तियां जरूर बसाई हैं- गांधीनगर, नया रायपुर और यहां तक कि भुवनेश्वर भी। लेकिन ये महज सरकारी कामकाज के केंद्र हैं। स्वतंत्र भारत में हमने केवल एक नया शहर बसाया है- चंडीगढ़, जिसे पांच लाख लोगों की आबादी के लिए



डिजाइन किया गया था। आज वहां शायद 14 लाख लोग रहते हैं। व्यावहारिक रूप से मेरा गृहनगर होने के बावजूद इसे वास्तव में एक शहर नहीं कहा जा सकता।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स (आईआईएचएस) की ओर से 15वें वित्त आयोग को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से बसाए गए सभी शहरों में कुल मिलाकर अधिकतम 13 करोड़ लोग ही रहते हैं। इनमें से ज्यादातर शहर मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारों और घरेलू सहायकों के लिए बनाई गई बड़ी-बड़ी सरकारी कॉलोनियां भर हैं। यहां न तो कारोबार हैं, न उद्यमिता और न ही सांस्कृतिक गतिविधियां। इन सबके लिए पास के किसी पुराने शहर का रुख करना पड़ता है।

शहरों पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना हमेशा संसाधनों की बरबादी माना गया, यही वजह है कि मौजूदा शहर समय के साथ जर्जर होते चले गए। इस बीच लाखों लोगों के गांवों से इन्हीं शहरों की ओर पलायन करने से भारत का शहरीकरण होता रहा। इनमें से ज्यादातर लोग झुग्गी-बस्तियों में रहने लगे जिन पर धीरे-धीरे माफिया का नियंत्रण हो गया।

मुंबई में जिसे झुग्गी-बस्ती कहा जाता है दिल्ली में उसे 'अनधिकृत कॉलोनियां' कहा जाता है। हर राजनीतिक दल इन कॉलोनियों को नियमित करने का वादा करता है। लेकिन इनके निवासी खुले नालों और गंदगी के बीच रहने के लिए अभिशप्त हैं। मुंबई अपनी जर्जर पुरानी मिलों और झुग्गी-बस्तियों को खत्म कर उनकी जगह नए निर्माण कर रहा है। वह एक नया उपनगर नवी मुंबई भी विकसित कर रहा है। ट्रांस-हार्बर लिंक के जरिये द्वीपीय शहर मुंबई को मुख्य भूमि से जोड़ा जा रहा है। यह परियोजना अभी निर्माण और विकास के दौर में है। दिल्ली ने गुरुग्राम और नोएडा में बड़े-बड़े उपनगरों को विकसित होने दिया। नतीजा यह हुआ कि तीनों शहरों के बीच लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के कारण आवागमन और यातायात की गंभीर समस्या पैदा हो गई। हालांकि दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपनी अनधिकृत कॉलोनियों में अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर है।

संजय गांधी ने इन बस्तियों को एक अपेक्षाकृत आकर्षक नाम दिया था- 'जेजे कॉलोनियां', यानी झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियां। इनमें से कई बस्तियों का आंशिक रूप से कायाकल्प हुआ लेकिन वहां नगरपालिका की सुविधाएं या तो बेहद सीमित हैं या बिल्कुल नहीं हैं। सत्य निकेतन भी ऐसी ही एक बस्ती है जहां सितंबर में एक इमारत ढहने से सात छात्रों की मौत हो गई थी।

बेंगलूरु का बेतरतीब विस्तार हुआ है लेकिन इसकी कुछ सबसे अमीर कॉलोनियां बाढ़ के पानी में दूसरी मंजिल तक डूब जाती हैं जबकि साल के बाकी समय शहर पानी के लिए तरसता रहता है। वहां टैंकर माफिया राज करता है। कोलकाता के बाहरी इलाकों में हुए कुछ नए विकास को छोड़ दें तो वहां शायद ही किसी इलाके को झुग्गी-बस्ती कहकर अलग से पहचाना जा सकता है। इसकी अधिकांश आबादी आज भी लगभग उसी स्तर की जीवन परिस्थितियों में रहती है।

नायडू से कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने शहर पर ध्यान केंद्रित करके गलती की है। इनमें हमारे 'पुराने विचारों वाले' समाजवादी टिप्पणीकारों का एक बड़ा वर्ग भी शामिल था। उनका आरोप था कि नायडू मुख्यमंत्री के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह काम कर रहे हैं और गरीबों की अनदेखी कर रहे हैं।

2019 के चुनावी झटके के बावजूद अमरावती को लेकर उनकी जिद इस बात का प्रमाण मानी जा रही है कि वे धुन के पक्के हैं और आसानी से रास्ता बदलने वाले नहीं हैं। देश में बुनियादी ढांचा तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण है। फिर अमरावती में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुए?

नायडू का पहला नवाचार जमीन पूलिंग योजना थी। किसानों को जमीन बेचने के बजाय उसे एक पूल में देने के लिए आमंत्रित किया गया। वादा किया गया कि हर एकड़ जमीन के बदले किसानों को विकसित आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों में एक निश्चित हिस्सा वापस दिया जाएगा। नायडू ने किसानों को सालाना निश्चित आय देने का वादा किया। इसकी शुरुआत प्रति एकड़ 50,000 रुपये सालाना से होनी थी जिसमें हर साल पांच फीसदी की बढ़ोतरी की व्यवस्था थी।

'घटती आबादी' और ए.आई. का डर

क्षमा शर्मा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बच्चों से ज्यादा होने पर स्थानीय निकायों के चुनाव न लड़ पाने के 2003 में दिए गए हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को आज के दौर में अप्रासंगिक बताया, क्योंकि भारत में जनसंख्या दर गिरकर 1.9 रह गई है। यानी कि अब प्रति दम्पति 2 से कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, जबकि 2003 में यह दर प्रति युगल 3 थी। आंकड़े बताते हैं कि जब प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ जाए तो जनसंख्या घटने लगती है। यही भारत में हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जनसंख्या नीति पर बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जनसंख्या गिर रही है। कुछ साल पहले टैस्ला और स्पेस एक्स के मालिक मशहूर अमरीकी उद्योगपति एलन मस्क ने कहा था कि दुनिया की आबादी बहुत कम है। यदि किसी बाहरी ग्रह से धरती पर आक्रमण होता है, तो धरती पर जनसंख्या खत्म हो सकती है। पिछले कई दशकों से भारत की बढ़ती आबादी और लगातार कम होते संसाधनों पर बात की जाती रही है। 'हम दो हमारे दो' के नारे को मध्यम वर्ग ने तो अर्से से अपना रखा है। वह वक्त भी रहा है जब किसी के 2 से अधिक बच्चे होते थे, तो उसका सार्वजनिक मजाक बनाया जाता था। यह वह दौर था, जिसमें अधिकांश युवा बड़े-बड़े संयुक्त परिवारों से आए थे। बड़े परिवार की शक्ति को पहचानते थे। किसी मुश्किल के वक्त, आम तौर पर परिवार एक-दूसरे के काम आते थे। लेकिन बढ़ी आबादी के खर्चे कैसे चलें, इसे लेकर इतना डर बैठाया गया कि लोग बच्चों को सबसे बड़ा खलनायक भी मानने लगे। जैसे कि बच्चे आएंगे तो सारी सुख-सुविधाओं में खलल पड़ जाएगा। आबादी के कारण ही इस देश की सारी मुसीबतें हैं। लेकिन अब इस विचार को सिर के बल खड़ा किया जा रहा है। दक्षिण में तो लगातार कम होती आबादी पर चिंता प्रकट की जा रही है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तो दूसरे बच्चे पर 25,000, तीसरे पर 30,000 और चौथे पर 40,000 रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। यह बात तब है, जब भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और अब तो अधिकांश युवा एक ही बच्चे को चाहते हैं। इसका एक बड़ा कारण वे बताते हैं कि इन दिनों बच्चे को पालना, उसे पढ़ाना-लिखाना, किसी योग्य बनाना बेहद खर्चीला है। नौकरियों का कोई भरोसा नहीं। ऐसे में यदि यह कहा जाने लगे कि आबादी कम हो चली है, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा होने चाहिएं, तो कुछ आश्चर्य भी होता है। ये बातें सिर्फ भारत में ही नहीं कही जा रहीं, दुनियाभर में बहुत से देश अपने-अपने यहां की घटती आबादी से परेशान हैं। चीन, जापान, रूस आदि अनेक देश अपने यहां के लोगों से कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करें। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। युवा जोड़े बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते। एक समय में चीन ने बढ़ती आबादी के कारण बहुत कठोर, एक बच्चा नीति अपना रखी थी। लेकिन अब वही चीन युवाओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए तरह-तरह से प्रोत्साहन दे रहा है। यहां तक कि डेटिंग के लिए विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। छुट्टियां दी जा रही हैं लेकिन युवा सरकार की बातें मानने को तैयार नहीं हैं। वे अधिक बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते। लड़कियां तो चुनौती देती कह रही हैं कि क्या हम कोई बच्चे पैदा करने की मशीनें हैं? ज्यादा बच्चे होंगे तो पालने हमें ही पड़ेंगे। रूस में तो 10 से अधिक बच्चों को जन्म देने वाली मां को सम्मानित किया जा रहा है। पश्चिमी देश भी जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर की सरकारों के सामने चुनौती है कि यदि नई पीढ़ी जन्म नहीं लेगी, तो देशों की आर्थिकी चलेगी कैसे? काम कौन करेगा? हालांकि दुनिया में बहुत से विरोधाभास दिखते हैं। एक तरफ तो कम आबादी की बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ए.आई. का ढोल पीटा जा रहा है। एलन मस्क ही बता रहे हैं कि कुछ सालों में किसी भी आदमी को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग काम जरूरत के लिए नहीं, शौकिया किया करेंगे। सारा काम ए.आई. संभाल लेगी। यहां तक कि पैसे की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी।

किसके फायदे के लिए बना चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का मोर्चा

यशोदा श्रीवास्तव

आजाद समाज पार्टी और एम.आई.एम.आई.एम. के बीच जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन हुआ है, वह समाज में क्या परिवर्तन ला पाएगा यह तो नहीं पता लेकिन यू.पी. विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन की चुनावी बिसात को गड्डु-मड्डु तो कर ही सकता है। ओवैसी की शिनाख्त भले ही भाजपा के हितैषी के रूप में है लेकिन हैदराबाद के बाहर के प्रदेशों में जहां वह चुनाव मैदान में उतरते हैं, 2-3 प्रतिशत मुस्लिम वोट पा ही जाते हैं। इतना ही प्रतिशत वोट भाजपा को तमाम सीटों पर फायदा पहुंचाने के लिए काफी है।

अब जब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण ओवैसी के साथ आ गए हैं, तो मुमकिन है उन पर भी भाजपा का सहयोगी होने की तोहमत लगने लगे। इस मोर्चे के उदय से पहले खबर आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी दोनों ही यू.पी. में 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा होने की इच्छा जाहिर कर चुके थे लेकिन सपा और कांग्रेस दोनों ही की ओर से तवज्जो नहीं दी गई।

इस मोर्चे को लेकर सपा और कांग्रेस ऊपर से भले ही बेफिक्र दिख रही हों, अंदरखाते उनमें हलचल तो मची ही हुई है। विधानसभा चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए हजार-दो हजार वोट काफी होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भले ही हैदराबाद के हों लेकिन उनके मुरीद मुस्लिमों का एक वर्ग देश के सभी प्रदेशों में मिल जाएगा भले ही मुट्ठी भर ही क्यों न हो। यू.पी. में आजाद समाज पार्टी के नेता व सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की दलित समाज के युवाओं में दीवानगी जैसी पैठ बढ़ रही है।

जाति विशेष की राजनीति करने वाले



इन दोनों नेताओं के मोर्चा गठित कर और यू.पी. के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लडने के ऐलान का निहितार्थ जो भी हो लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बनने का दावा हास्यास्पद लगता है। यह न तो ओवैसी के लिए संभव है और न ही चंद्रशेखर रावण के लिए।

यू.पी. विधानसभा चुनाव से पहले दलित-मुस्लिम गठबंधन का यह मोर्चा निश्चित ही यू.पी. में इन दो प्रमुख जातियों के दम पर कामयाबी का ख्वाब देखने वाले दलों के लिए ड्क्षचता का सबब है। अपने प्रदेश में महज 7-8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लडने वाले ओवैसी दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और भाजपा से मुकाबला करने वाली पार्टियों का खेल खराब कर देते हैं। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण के आ जाने से उनकी राजनीति के असल मकसद का पर्दाफाश हुआ है। इस नए गठबंधन के उदय पर भाजपा खामोश है, वहीं सपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें इस गठबंधन को भाजपा का मददगार बताया गया है। प्रथम दृष्टया यह सच भी हो सकता है क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के लिए केवल वोटरों के भरोसे नहीं रहती, वह हर हथकंडा अपनाती है, जो उसके लिए चुनावी दृष्टि से फायदेमंद हो। उसमें जातीय समीकरण साधने से लेकर नए-नए गठबंधन का सृजन भी शामिल है। मुमकिन है यू.पी. में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण के मोर्चे के पीछे भी भाजपा हो लेकिन यदि ऐसा है तो यह सब जोड़-घटाना गैर-भाजपा दल क्यों नहीं कर पाते? ओवैसी ने तो अपने गठबंधन में सपा और कांग्रेस को शामिल होने का न्यौता देकर गेंद उनके पाले में डाल दी है। हालांकि भाजपा की बी टीम होने की तोहमत से बचने के लिए यह उनकी एक चाल के सिवा कुछ नहीं। यू.पी. में चुनाव पूर्व पैदा हुआ यह मोर्चा ज्यादा नहीं 50 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में 6-7 हजार वोट ही पाने में सफल रहा तो विपक्ष का खेल खत्म।

मालूम हो कि एक वक्त था जब कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले दलित और मुस्लिम इकट्ठा हुए थे। इसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा 3 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। वहीं मुस्लिम समाज जब समाजवादी पार्टी के खेमे में चला गया, तब यादव-मुस्लिम के समीकरण से सपा भी 4 बार सरकार बनाने में कामयाब रही। यू.पी. में कांग्रेस के कमजोर होने का फायदा बसपा और सपा को खूब मिला। यदि पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम पर गौर करें तो पता चलता है कि दलित समाज, खास कर इस समाज के युवा बाबा साहेब डाक्टर भीमराव आंबेडकर के संविधान की रक्षा को लेकर काफी जागरूक दिखे। सपा और कांग्रेस ने संविधान पर खतरे का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था, नतीजा दलित वोटरों ने सपा और कांग्रेस को भर-भर कर वोट दिए, साथ में मुस्लिम वोटरों की एकजुटता भी कमाल की थी।

लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को अच्छी-खासी कामयाबी मिली, भाजपा पीछे छूट गई। 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम वोटरों में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा, वे सपा और कांग्रेस के साथ अभी भी दिख रहे हैं लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क यह है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम लाखों वोटरों में तय होता है जबकि विधानसभा चुनाव परिणाम अधिकतम 1 लाख वोटों में ही वारा-न्यारा हो जाता है और दो-तिहाई से अधिक सीटों पर 2 से 10 हजार वोटों के अंतर से ही हार-जीत का फैसला होता है।

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी-अपनी जातियों पर जाल फैंक दिया है, अब फंसते कितने हैं, यही देखना है। जितना अधिक फंसेंगे, सपा व कांग्रेस के सामने उतनी ही मुश्किलें आएंगी। 2022 के चुनाव में रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर आजाद समाज पार्टी ने 0.13 प्रतिशत वोट हासिल किया था, वहीं इसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 0.49 प्रतिशत वोट हासिल हुआ था। अलग-अलग लड़े इन दोनों पार्टियों को मिला वोट भले ही आंकड़ों में भारी न हो लेकिन अकेले चुनाव मैदान में उतरी सपा को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा था।

'बिलॉन्गिंग': प्रेम, पीड़ा और कटुता की गाथा

प्रभु चावला

किसी भी राजनेता का संस्मरण केवल अतीत को याद करने का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह एक तरह से सत्ता और इतिहास को अपने पक्ष में ढालने का प्रयास भी होता है। यह शब्दों की बाजीगरी भी हो सकती है और राजनीतिक रणनीति भी। कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने मजाक में कहा था कि इतिहास उनके प्रति उदार रहेगा, क्योंकि वे स्वयं इतिहास लिखने जा रहे हैं।

उसके बाद से नेताओं ने इस संकेत को अच्छी तरह समझ लिया। जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक शासन के दौरान जेल में अपनी आत्मकथा लिखी और अपनी कैद को एक ऐसे आधारभूत दस्तावेज में बदल दिया, जिसने एक राष्ट्र की आत्मछवि गढ़ने में भूमिका निभाई। राजनीतिक संस्मरण महज यादों का संकलन नहीं होता।

यह एक ऐसा चुना हुआ अभिलेख होता है, जिसमें लेखक तय करता है कि क्या याद किया जाएगा, किस घटना को किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और किस बात को भुला दिया जाएगा। किसी राजनीतिक परिवार या वंश में इसके मायने और भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी किताब केवल लेखक के जीवन का बचाव नहीं करती, बल्कि पूरी विरासत का बचाव करती है।

इसे जितना पाठकों के लिए लिखा जाता है, उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी। सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग = ए जर्नी ऑफ लव', (अपनापन = प्रेम की एक यात्रा), जो पिछले दिनों प्रकाशित हुई, इसी परंपरा का हिस्सा है। इसकी प्रस्तावना में इसे 'एक व्यक्तिगत संस्मरण'



कहा गया है, जिसके लिए राजनीति पृष्ठभूमि का काम करती है।

लेकिन यह पृष्ठभूमि आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक तूफान का रूप ले लेती है। एक ऐसी महिला, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सक्रिय राजनीति से पीछे हट चुकी हैं, उन्होंने इस दौर का सबसे विस्फोटक राजनीतिक दस्तावेज पेश कर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पुस्तक का अधिक ईमानदार शीर्षक शायद होता- अपनापन = प्रेम, पीड़ा और कटुता की गाथा।

यह पुस्तक अपनी खूबियों के लिए तारीफ की हकदार है। इसकी प्रेम कहानी बेहद खूबसूरती से लिखी गई है। इसकी शुरुआत होती है इस दृश्य से- एक लंबा और आकर्षक नौजवान, जिसकी आंखें गहरी काली थीं, कमरे के दूसरी ओर दिखाई दिया। यह कैम्ब्रिज का एक ग्रीक रेस्तरां 'द वर्सिटी' था, और 1960 के दशक के मध्य में पूरे शहर में यही एकमात्र जगह थी, जहां कुछ-कुछ इतालवी शैली का भोजन मिलता था।

इसके बाद जो कहानी सामने आती है, वह किसी निजी पारिवारिक एलबम के खुलने जैसी लगती है। लेकिन इस प्रेम कहानी में पीड़ा के दो ऐसे प्रसंग आते हैं, जो हृदय को झकझोर देते हैं। पहली त्रासदी अक्तूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के साथ घटित हुई। दूसरी त्रासदी 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के समय सामने आई।

उस रात की बची हुई चीजों को देखते हुए सोनिया को परिवार की वे तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें राजीव हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्हें एक थैला भी मिलता है, जिसमें वे कपड़े थे जिन्हें राजीव ने हत्या होने से पहले बदला था। वे लिखती हैं- 'मैं उस थैले पर झुक जाती हूं और अपने प्रिय की उस धुंधली पड़ चुकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करती हूं, जो हमेशा के लिए जा चुका है।'

बहुत कम भारतीय राजनीतिक संस्मरणों में निजी दुख और बिछड़ने की पीड़ा को इतनी गहराई और संवेदनशीलता से व्यक्त किया गया है। इसके बाद पुस्तक में एक बदलाव आता है। शोक की जगह शिकायतें ले लेती हैं। आपातकाल का उल्लेख बेहद सावधानी से किया गया है। संजय गांधी के बारे में वे लिखती हैं कि उनका नाम 'आपातकाल का पर्याय बन गया था।'

इसके विपरीत, राजीव गांधी को परिवार की अंतरात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी मां उनसे कहती हैं, 'तुम्हारी सहज समझ सही है, राजीव।' किसी को कोई संदेह न रहे, इसलिए सोनिया स्पष्ट करती हैं कि राजीव का 'आपातकाल से कोई लेना-देना नहीं था।' इसी तरह की बचावपूर्ण भाषा 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के संदर्भ में भी दिखाई देती है।

लेकिन केवल किसी के चरित्र के बारे में दावा करना, उसके पक्ष में सबूत नहीं होता। अगर इस पुस्तक का मकसद कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि को फिर से मजबूत करना और भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में लाना था, तो इसका उल्टा ही हुआ है। पुस्तक के प्रकाशन के एक दिन के भीतर ही भाजपा नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सोनिया गांधी की आंखों में बाबरी मस्जिद के लिए आंसू हैं,

लेकिन गोधरा के लिए वे आंसू कहां गायब हो जाते हैं? उन्होंने आपातकाल से जुड़े विवरण को भी एक पारिवारिक झगड़े के रूप में पेश किया - एक भारतीय छोटी बहू और विदेशी मूल की बड़ी बहू के बीच विवाद के रूप में। इस तरह एक ही राजनीतिक तंज ने विदेशी मूल का पुराना विवाद फिर से जीवित कर दिया।

आपातकाल, 1984 के सिख नरसंहार, शाह बानो कांड, बोफोर्स कांड और मुस्लिम तुष्टिकरण एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि यह किताब भाजपा को उसका सबसे मजबूत आरोप सौंपती है- कि कांग्रेस गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही कांग्रेस है। एक ऐसी कहानी में जहां हर नायक परिवार का सदस्य है और हर असफलता किसी बाहरी व्यक्ति की है,

यह आरोप सही साबित होता है। राहुल गांधी, जिन्हें 2029 में पार्टी का नेतृत्व करना है, न केवल एक विरासत बल्कि एक सुनियोजित पांडुलिपि के उत्तराधिकारी हैं। प्रेम कहानी और शोक की अभिव्यक्ति के रूप में 'बिलॉन्गिंग' बेहद सफल साबित होती है। इतिहास के रूप में, यह बचाव पक्ष की दलील है, जिसे प्रतिवादी के परिवार ने लिखा है। राजनीति के रूप में, यह साबित कर सकती है कि किसी नेता द्वारा लिखी गई सबसे खतरनाक किताब वह होती है, जो देश को उन तमाम बातों की याद दिला दे, जिन्हें वह भुला देना चाहता था।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर स्पष्ट किया रुख

संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान जारी रखना चाहता है। यह पहली बार नहीं है, जब नई दिल्ली ने ऐसा रुख अपनाया है। इससे पहले 2016, 2018 और 2024 में भी संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने संबंधी प्रस्तावों के खिलाफ भारत ने मतदान किया था। इसके पीछे भारत के ठोस तर्क हैं।



पहला, प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक प्रणाली और दंड विधान तय करने का अधिकार है, और इसे बाहरी रूप से थोपा नहीं जा सकता। दूसरा, मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने या इस पर रोक लगाने को लेकर कोई वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय सहमति मौजूद नहीं है। यहां तक कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद-6 भी कुछ शर्तों के साथ मृत्युदंड की अनुमति देता है।

भारत में मृत्युदंड कानूनन वैध है और उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। ऐसे में, इसे राज्य प्रायोजित हत्या कहना न्यायिक व्यवस्था और विधि के शासन की अनदेखी करना होगा। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी देकर मृत्युदंड देने की प्रक्रिया को असांविधानिक घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह भारतीय कानून के तहत मृत्युदंड देने का एक वैध और कानूनी तरीका है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में केवल दुर्लभतम मामलों में ही अदालतों द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मेक्सिको की ओर से पेश किए गए 'मृत्युदंड पर रोक' संबंधी प्रस्ताव पर मतदान से स्पष्ट है कि इस मामले में दुनिया दो स्पष्ट धड़ों में बंट चुकी है। एक ओर बड़ी संख्या में देश इसे समाप्त कर चुके हैं, या इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश इसे गंभीर अपराधों के लिए जरूरी दंड मानते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में भी दुनिया के 17 देशों में करीब 2,707 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई। यह स्थिति दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड की सजा के खिलाफ कोई आम सहमति नहीं है। ऐसे में, मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव का समर्थन न करना भारत का अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श से अलग होना नहीं है। यह केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संप्रभु अधिकारों के प्रति उसके पुराने और दृढ़ रुख की एक स्वाभाविक निरंतरता है।

सर्दियां आते ही स्किन हुई बेजान? इन 6 आसान घरेलू नुस्खों से पाएं गुलाबी निखार



सर्दियां आते ही स्किन नमी खोने लगती है और शरीर में रूखापन, खुजली और फटी त्वचा की समस्या बढ़ने लगती है। सर्द हवाएं और कम नमी वाला वातावरण स्किन की नेचुरल ऑयल लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे स्किन डल और ड्राई हो जाती है। इस मौसम में स्किन को हाइड्रेट रखना काफी जरुरी होता है। अगर आप बाजार के केमिकल युक्त बॉडी लोशन लगाएं तो इससे आपकी स्किन चमक खो देगी। इसके बजाय आप प्राकृतिक चीजें जैसे कि नारियल तेल, एलोवेरा जेल, दूध, शहद और घी त्वचा के अंदर से पोषण प्रदान करके स्किन को सॉफ्ट बनाता है। आइए आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा और बॉडी के रुखेपन और जलन को हटाएगा।

विंटर ड्राईनेस से बचने के लिए 6 घरेलू चीजें

नारियल तेल

कोकोनट ऑयल स्किन को बेहतरीन नेचुरल मॉइश्चराइजर है। नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड होते हैं जो त्वचा की नमी को बनाए रखता है। स्नान के बाद हल्का सा नारियल तेल पूरे शरीर पर लगाएं।

सरसों का तेल

हर भारतीय घर में सरसों का तेल पारंपरिक तरीका है जो सर्दियों में स्किन को गर्मी और नमी देता है। प्रतिदिन नहाने से पहले हल्का गुनगुना तेल शरीर पर लगाएं इसके बाद स्नान करें।

एलोवेरा जेल

स्किन को हाइड्रेट करता है एलोवेरा जेल, इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसे रोज नहाने के बाद स्किन पर नमी बरकरार रखने के लिए और खुजली की समस्या को दूर करता है।

दूध और शहद

वैसे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है और शहद नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। दोनों को मिलाकर हल्का मसाज करें और इसे 15 मिनट बाद धो लें।

घी

घी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, इसे खासकर कोहनी, घुटनों और एड़ियों पर लगाने से रूखापन और स्किन फटने की समस्या दूर हो जाती है।

ओट्स और दही

ड्राई स्किन की समस्या को दूर करने के लिए यह नुस्खा बेहद कमाल का है। यह प्रकार का नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है। ओट्स पाउडर और दही मिलाकर लगाएं, 15 मिनट बाद इसे धो लें, आपकी त्वचा सॉफ्ट होती है।

इन चीजों का ध्यान रखें

» दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं जिससे आपका शरीर अंदर से हाइड्रेट रहेगा।

» बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें, यह आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल परत को नुकसान पहुंचाता है।

» डेली मॉइश्चराइजर लगाएं और कॉटन के कपड़े पहनें।

लौकी-तोरई से ऊब गए? बनाएं ये झटपट कॉर्न कोफ्ता, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे!



रोजाना हर घर में होता है कि नाश्ता, लंच और डिनर में क्या बनाएं। रोज जो खाने में बनता है बच्चे भी खाने में कमी निकालने लगते हैं। लौकी-तोरई खाकर सब पक भी जाते हैं। इस वजह से आजकल मम्मियां भी सब्जियों को अलग-अलग तरीके से ट्राई करके डिशेज बना सकती है। बाजार में कई तरह की सब्जियां मिलती है, अगर आप बार-बार वहीं सब्जियां खाकर पक गए हैं, तो घर पर ट्राई करें कॉर्न कोफ्ता की सब्जी। कॉर्न कोफ्ता करी बनाना बेहद आसान है। आइए आपको कॉर्न कोफ्ता की रेसिपी के बारे में बताते हैं।

कॉर्न कोफ्ता करी कैसे बनाएं

» सबसे पहले आप कॉर्न कोफ्ता बनाने के लिए पकोड़ो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

» इसके लिए आप कॉर्न को कद्दूकस कर लें।

» अब आप पल्प को बाउल में निकाल कर आधा हिस्सा प्लेट में रख लें।

» इसमें अब बेसन डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल बना लीजिए।

» अब 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 4-5 बड़े चम्मच हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

» 2-3 मिनट तक घोल को साइड में रख लें और अब कड़ाही में तेल गर्म कर लें।

» अब आप छोटे-छोटे या अपने मनपसंद आकार में पकोड़े बनाकर तैयार कर लें।

ग्रेवी को कैसे बनाएं

» ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सर जार में 5 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक डालें और इसे बारीक पीस लें।

» इसके बाद पेन में 2-3 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डालें और इसे भून लीजिए।

» अब टमाटर का पेस्ट डालें और इसे धीरे-धीरे चलाते रहे हैं। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिला लें और इसे थोड़ी देर तक चलाते रहे हैं।

» मसाले के आधा पक जाने पर इसमें बचाया हुआ ग्रेट भुट्टा और 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिला दीजिए।

» जब उबाल आए तो इसे थोड़ी देर चलाते हुए 5 मिनट तक और पकाएं। ग्रेवी गाढ़ी होने पर बनाएं हुए पकोड़े डाल दें।

» इसके बाद करी को 5 मिनट तक और पकाएं, इसमें 1 छोटी चम्मच घी डाल कर अच्छा से मिलाकर फ्लेम बंद करें।

» यह लीजिए तैयार है आपकी कॉर्न कोफ्ता करी। इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।

कॉर्न कोफ्ता बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

» कॉर्न कोफ्ता करी बनाने के लिए आप बेबी कॉर्न को चूज करें।

» मसाला को लो फ्लेम पर ही बनाएं।

» कोफ्ता के पकोड़े बनाते समय गैस को लो फ्लेम पर पकाए और चलाते हुए जरुर पकाएं।

मेहमानों को खिलाएं 5 फ्लेवर का पोटली समोसा, हर कोई पूछेगा रेसिपी

समोसा खाना लगभग हम सभी को पसंद होता है। यह एक परफेक्ट स्नैक है, लेकिन अगर आप भी आलू वाला समोसा खाकर बोर हो गई हैं। तो अब आप थोड़ा नया और मजेदार पोटली समोसा ट्राई करें। जितना प्यारा इसका नाम है, उतना ही इसका लुक और टेस्ट भी लाजवाब होता है। गोल-गोल छोटी पोटली जैसी शेप में बना यह समोसा अंदर से टेस्टी और क्रिस्पी होता है। खास बात यह है कि आप इसको 5 अलग-अलग फ्लेवर में तैयार कर सकती हैं। जिससे कि हर बार इसका स्वाद अलग और नया लगे। आप त्योहारों में इसको स्नैक्स की तरह भी बना सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कौन-कौन से फ्लेवर में पोटली समोसा बनाकर तैयार कर सकती हैं। वहीं यह मेहमानों को भी बेहद पसंद आएगा।

आलू मसाला पोटली समोसा

आलू मसाला वाला पोटली समोसा सबसे पसंदीदा और क्लासिक फ्लेवर है। इसको बनाने के लिए उबले आलू, हरी मिर्च, मटर, अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाकर फिलिंग तैयार कर लें। अब पतली मैदा की पोटली बनाकर फीलिंग करें और इसके किनारे को पोटली शेप दें। अब तेल में इसको सुनहरा होने तक तलें। इस समोसे का स्वाद करीब-करीब हर किसी को पसंद आएगा।

पनीर पोटली समोसा

अगर आप भी रिच फ्लेवर चाहती हैं, तो आपको एक बार पनीर पोटली समोसा ट्राई करना चाहिए। इसके लिए पनीर को मैश या ग्रेट करके इसमें हरी मिर्च, धनिया, प्याज और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें चीज भी मिला सकती हैं। अब इसको पोटली की तरह बंद कर दें। यकीनन पनीर पोटली समोसा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

वेज मिक्स पोटली समोसा

अगर आपके बच्चे भी सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, तो आप उनको वेज मि?क ?स पोटली समोसा बनाकर खिला सकती हैं। इसको बनाने के लिए बीन्स, मटर, गाजर, पत्तागोभी और कॉर्न जैसी सब्जियों को बारीक काटकर हल्का भून लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा सोया सॉस डालें। यह फ्लेवर इंडो चाइनीज जैसा लगेगा। वहीं बच्चे भी इसको स्वाद लेकर खाएंगे।



ड्राई फ्रूट्स वाला पोटली समोसा

अगर आप भी त्योहारों के मौसम में मेहमानों और बच्चों को कुछ रॉयल बनाकर खिलाना चाहती हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स वाला पोटली समोसा ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए बादाम, किशमिश, काजू, खोया और इलायची पाउडर मिलाकर स्टफिंग तैयार करें। फिर इसकी पोटली बांधकर घी में फ्राई करें। फिर ऊपर से शहद या फिर चीनी की हल्की चाशनी डाल दें। यह मीठा पोटली समोसा खाने में बेहद टेस्टी होता है।

चीज-गार्लिक पोटली समोसा

अगर आप चीज लवर हैं, तो चीज-गार्लिक पोटली समोसा आपके लिए बना है। इसके लिए बटर में थोड़ा सा लहसुन भून लें और लहसुन को मैश करके इसमें ओरेगानो, चीज और थोड़ा सा नमक मिलाएं। ये स्टफिंग पोटली समोसे को जबरदस्त टेस्ट देगा। इसको डीप फ्राई करें और सर्व करें। वहीं बच्चों को चीज गार्लिक पोटली समोसे का स्वाद काफी पसंद आएगा।

अलमारी में बंद ऊनी कपड़ों से आती है बदबू? इन 5 तरीकों से घर बैठे बनाएं खुशबूदार



धीरे-धीरे सर्दियां दस्तक दे रही है। अब मौसम में भी काफी बदलाव आ रहा है। हल्की से ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में लोग बंद रखे हुए ऊनी कपड़ों को निकाल रहे हैं। सर्दियों को ऊनी कपड़े सिर्फ साल के दो या 3 महीने पहने जाते हैं। बाकी पूरे साल तो ये कपड़े आलमारी, बक्से, बेडबॉक्स में ही बंद पड़े रहते हैं। जिस वजह से इनमें बदबू भर जाती है। अक्सर होता है कि ऊनी कपड़े जब बक्से और वॉर्डरोब से निकाले जाते हैं तो अंजीब से बदबू आने लगती है। कभी ऊनी कपड़े साफ ना होने की वजह से पसीना और बैक्टीरिया के साथ सीलन की बदबू भर जाती है। ऐसे में बदबूदार ऊनी कपड़ों, जैकेट, शॉल को पहनना मुश्किल हो जाता है। आइए आपको इन 7 घरेलू तरीकों से ऊनी स्वेटर, जैकेट से आने वाली बदबू को दूर करें।

धूप सबसे बेहतर है

अगर आप ऊनी कपड़ो को बदबू को दूर करना चाहते हैं, तो धूप सबसे सरल और सस्ता उपाय है। वुलन क्लॉथ को धूप में डालने से कपड़ों से दुर्गंध चली जाएगी। कपड़ों पर धूप लगने से नमी, बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। जिससे बदबू भी निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी तेज धूप हो तो कपड़ों को उल्टा करके रखें। वरना कपड़ो का रंग उड़ सकता है।

बेकिंग सोडा का यूज करें

यदि आप वुलन कपड़े आलमारी में रखने से इनमें सीलन और फफूंद लग गई है, तो कपड़ों से आ रही इस तरह की बदबू को दूर भगाने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर कपड़ो को डालकर निकाल दें। यदि आपके पास कपड़ों को धोने का टाइम नहीं है, तो बेकिंग सोडा को कपड़ो पर छिड़कर कुछ देर छोड़ दें और बाद में सूखे कपड़े से साफ कर दें।

वुलन्स पर करें नेचुरल फ्रेशनर का स्प्रे

अगर ऊनी कपड़ों से स्मेल आ रही है, तो इसे दूर करने के लिए नेचुरल फ्रेशनर का स्प्रे बना लें। एक स्प्रे बोतल में पानी भर लें, उसमें एक नींबू का रस और दो से तीन चम्मच गुलाबजल के डाल दें। मिक्स करके इसे ऊनी कपड़ों पर छिड़काव कर दें। इस तरह के स्प्रे से वुलन जैकेट, स्वेटर सबसे नेचुरल भीनी सी स्मेल आएगी और आपके कपड़े भी फ्रेश महकेंगे।

कपूर का करें यूज

वुलन कपड़ों में किसी तरह की महक ना आए इसलिए जब भी इन्हें स्टोर करें तो कपूर लौंग की छोटी पोटली बांधकर वुलन्स के साथ रख दें। इसकी महक कपड़ों में फ्रेशनेस बनाकर रखेगी।

एसेंशियल ऑयल का स्प्रे

अगर आप भी वुलन स्वेटर, जैकेट, शॉल जैसे कपड़ों से बदबू हटाने के लिए एसेंशियल ऑयल को आलमारी में रखें। इसके लिए आप किसी छोटे कपड़े के टुकड़ें में लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल की बूंदों को डालकर ऊनी कपड़ों के बीच रख दें। इससे भी वुलन्स के कपड़ों में आ रही बदबू को दूर भागने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राज्यसभा सदस्य के रूप में हरदीप पुरी ने ली शपथ

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। संसद भवन में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को संसद भवन में अपने कक्ष में हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुरी मध्य प्रदेश से निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने उच्च सदन के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से पुरी का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है।

अभिषेक को हाईकोर्ट का नोटिस 15 दिन में देना होगा जवाब



कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया। यह नोटिस फेसबुक पर की गई एक ऐसी पोस्ट को लेकर है, जिसमें कथित तौर पर न्यायिक प्रणाली पर निशाना साधा गया था। अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने टीएमसी सांसद को दी गई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक मामले में अपना फैसला भी सुनाया। बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था के मुख्य मुद्दे पर गौर करते हुए, न्यायमूर्ति राव ने राज्य प्रशासन को कुछ विशेष निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल गृह विभाग और प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की एक बैठक बुलाएं, ताकि टीएमसी नेता की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों की अच्छी तरह से जांच और समीक्षा की जा सके।

केजरीवाल का शीशमहल आम जनता के लिए खोला जाएगा



नईदिल्ली। दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की है कि सिविल लाइंस स्थित विवादित आवास, शीश महल, जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्मा ने कहा कि यह फैसला जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों के लिए टिकट और बुकिंग की व्यवस्था शुरू करने से पहले, प्रशासन सबसे पहले राष्ट्रीय मीडिया को वहां जाने की अनुमति देगा। वर्मा ने कहा दिल्ली के लोग कई सालों से शीश महल देखना चाहते थे... पहले कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ था कि इस शीश महल को एक स्टेट गेस्ट हाउस में बदल दिया जाएगा। लेकिन, जनता की मांग को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि शीश महल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वहां जाने की प्रक्रिया, टिकट कैसे बुक करें और रिजर्वेशन कैसे कराएं। इस बारे में बाकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को राहत



नईदिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को मंगलवार (17 नवंबर 2026) को देश की सर्वोच्च अदालत से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत आज़म खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कानूनी राहत आज़म खान की पत्नी तज़ीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को भी प्रदान की है, जिन्होंने इस मामले में अलग-अलग अपीलें दायर की थीं। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद तीनों की दोषसिद्धि पर लगी रोक आगे भी जारी रहेगी, जबकि निचली अदालत से जुड़ी मुख्य कानूनी कार्यवाही समानांतर रूप से चलती रहेगी।

राहुल और अखिलेश की चर्चा के बाद टली कांग्रेस-सपा बैठक

नईदिल्ली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंगलवार को प्रस्तावित बैठक दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत के बाद टल गई है। अब यह बैठक कुछ दिनों बाद होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातचीत के दौरान सीट बंटवारे को लेकर एक ''मसौदे'' पर चर्चा हुई, हालांकि इसका विवरण अभी सामने नहीं आया है। सूत्रों ने बताया कि अब दोनों दलों के नेता इस मसौदे और अपनी ओर से निर्धारित फार्मूले के आधार पर आगे की बातचीत करेंगे। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम से इतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई। इस दौरान उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद दोनों दलों के बीच प्रस्तावित बैठक टालने का फैसला किया गया। अब नए मसौदे पर विचार-विमर्श के बाद दो-तीन दिन में दोनों पक्षों के नेताओं की बैठक हो सकती है।

आसियान समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी

हमारे पास सामर्थ्य भी और संकल्प भी



मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने लगातार कई संकटों का सामना किया है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा शांति, स्थिरता और भरोसेमंद माहौल की जरूरत है। ऐसे में इस वर्ष की थीम %हम सब मिलकर अपने भविष्य की राह तय करें% विशेष महत्व रखती है। आने वाले वर्षों में आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने कहा हमारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी जिससे हम आपसी भागीदारी को नई दिशा दे सकते हैं। हमारा मानना है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है। अब हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए नई दिशा तय करनी होगी। आसियान की एकता और इस साझेदारी में उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट है और आगे भी बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि आज की यह बैठक हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और एक सुरक्षित, समावेशी तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने भारत-आसियान संबंधों को नई गति और गहराई दी है। हमारी साझेदारी अब साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी नए आयाम हासिल कर चुकी है। वर्ष 2014 से अब तक लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की गई हैं, करीब 250 क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और कौशल विकास के लिए 10 हजार से अधिक छात्रवृत्तियां दी गई हैं। आज भारत और आसियान के नौ देशों के बीच सीधी उड़ानें और बढ़ता पर्यटन हमारे मजबूत संबंधों का प्रमाण हैं।

अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के इस समूह (क्वाड) की ये बैठक डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहली होगी। ये बैठक इस समूह के पिछले सम्मेलन के दो साल बाद हो रही है, जिसे उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन अपनी विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि मानते थे।

फिलीपींस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका और यहां उन्होंने ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और स्थानीय सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा-

महंगाई से लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री राजनीति में व्यस्त



नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई बेकाबू हो गई है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असंवेदनशीलता और अहंकार का आलम यह है कि इस संकट के बीच भी उन्हें सिर्फ राजनीति की चिंता है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट में एक सर्वेक्षण के हवाले से दावा किया गया है कि हर 10 में से छह परिवार एक साल पहले की तुलना में घरेलू सामान पर 20 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में लिखा, महंगाई से परिवार परेशान हैं और कारोबार बंद होने को मजबूर हैं! मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और जनविरोधी नीतियों ने महंगाई को बेकाबू कर दिया है। इससे आम जनता और कारोबारी दोनों की कमर टूट रही है। सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 61 प्रतिशत परिवारों का मासिक खर्च 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।

उन्होंने दावा किया कि 74 प्रतिशत लोग गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं, जबकि 50 प्रतिशत लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी भी कम करनी पड़ रही है। रमेश ने कहा कि पिछले एक साल में घी और खाद्य तेल की कीमतों में 75 प्रतिशत, सब्जियों में 73 प्रतिशत, चावल, गेहूं और अन्य अनाज में 71 प्रतिशत, दूध और डेयरी उत्पादों में 65 प्रतिशत तथा दालों की कीमतों में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि नोएडा में ही एक साल के भीतर 200 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रमेश ने इसके लिए अमेरिकी टैरिफ, कच्चे माल की ऊंची कीमतों और सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा पूरे देश में कपड़ा उद्योग की खराब स्थिति का संकेत है।

रमेश ने कहा, महंगाई के ये आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लोगों की थालियां छोटी हो रही हैं और फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता और अहंकार ऐसा है कि इस संकट के बीच भी उनकी एकमात्र चिंता राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो जनता की परेशानियों को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है और न ही उन्हें किसी तरह की राहत देने के लिए कदम उठा रही है।

पिछले सप्ताह भी कांग्रेस ने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी ने कहा था कि यह अमृत काल नहीं, बल्कि महंगाई का भूकंप है। कांग्रेस लगातार जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। पार्टी का कहना है कि बढ़ते घरेलू खर्च के कारण परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन की याचिका पर सुनवाई टली

ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर उठाए गए थे सवाल



नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख नौ दिसंबर तय की है। विपक्ष की तरफ से दाखिल नई अर्जी पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने नोटिस जारी करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान तय करेंगे। नई अर्जी के जरिए विपक्ष ने 48 सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से पूछने की इजाजत मांगी है।

बता दें कि सोमवार, 16 नवंबर को विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी।

संजय राउत माफी दिल से मांगें, दिमाग से नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को नसीहत दी है। आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। कोर्ट ने राउत को अनुभवी नेता और सांसद बताते हुए सार्वजनिक बयान देते समय संयम बरतने की सलाह दी।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबी) की ओर से पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका से जुड़ा है। दोनों पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, न कि दिमाग से। उन्होंने राउत से कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता और सांसद हैं। अदालत उनके भाषण पहले से सुनती रही है। वह खुद पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में किस तरह का संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि सम्मानजनक पद पर बैठे व्यक्ति से अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्तूबर को संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह मामला सीजेआई और न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।

खेल
प्रमुख समाचार

आईपीएल से महेंद्र सिंह धोनी ने लिया संन्यास



नईदिल्ली। आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है और अब वह मैदान पर खिलाड़ी के बजाय नई भूमिका में नजर आएंगे। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें आईपीएल 2027 से टीम का मेंटर बनाने का फैसला किया है। हालांकि, उनका फ्रेंचाइजी से जुड़ाव पहले की तरह बना रहेगा।

धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाया है। उनकी कप्तानी में टीम ने कई यादगार सफलताएं हासिल कीं। अब आईपीएल में उनका सफर बतौर खिलाड़ी खत्म हो गया है। वह टीम के डगआउट में मेंटर की भूमिका निभाएंगे और अपने अनुभव से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। धोनी का चेन्नई के साथ रिश्ता बेहद खास रहा है। वह फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुके हैं और उनके फैसलों तथा नेतृत्व क्षमता ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने भी धोनी के महत्व पर बात की है। उन्होंने साफ किया कि पूर्व भारतीय कप्तान हमेशा फ्रेंचाइजी की पहचान का अहम हिस्सा रहेंगे। खिलाड़ी के तौर पर उनकी भूमिका भले ही बदल रही है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका जुड़ाव पहले की तरह मजबूत बना रहेगा। धोनी के मेंटर बनने से टीम को उनके लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा। खासकर युवा खिलाड़ियों को उनके मार्गदर्शन में खेलने और सीखने का मौका मिलेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बाजार में जमकर हुई खरीदारी सेंसेक्स 427 अंक चढ़कर बंद

नईदिल्ली। शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 427 अंकों की उछाल के साथ 82532 पर बंद हुआ, जो सेशन के दौरान 82897 तक उछला और 82091 तक फिसला। निफ्टी भी 25501 से फिसलकर 25387 पर बंद हुआ है। हालांकि, ब्रॉडर मार्केट में मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। मिडकैप इंडेक्स हल्की बढ़त और स्मॉलकैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार में सबसे ज्यादा जोश सरकारी बैंक और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। वहीं, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव दिखा। निफ्टी में 50 में से 27 शेयर बढ़त और 23 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। अदाणी एंटरप्राइसेज 3.2 फीसदी की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। आयशर मोटर्स और मैक्स हेल्थ के शेयरों में 2 से 3 फीसदी तक की तेजी रही।

दिसंबर में आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) महंगाई पर काबू पाने के लिए आने वाले महीनों में रेपो रेट में 50 से 75 आधार अंक तक की बढ़ोतरी कर सकता है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि मौजूदा मौद्रिक सख्ती के दौर में रेपो रेट बढ़कर 6 से 6.25 फीसदी तक पहुंच सकता है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होगी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। दो साल में पहली बार महंगाई आरबीआई की निर्धारित 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से आगे निकली है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी इसका प्रमुख कारण रही। खाद्य महंगाई भी सितंबर के 7.74 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 फीसदी पर पहुंच गई। मॉर्गन स्टेनली को दिसंबर में रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

भारत का बागवानी उत्पादन 2025-26 में 4.36% बढ़ा

नई दिल्ली। भारत का बागवानी उत्पादन फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) में 4.36 प्रतिशत बढ़कर 38.69 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सरकार का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। यह उत्पादन 2024-25 में दर्ज 37.07 करोड़ टन से 1.61 करोड़ टन अधिक होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा कि बागवानी फसलों का रकबा एक साल पहले के 3.01 करोड़ हेक्टेयर से घटकर करीब 2.97 करोड़ हेक्टेयर रहने के बावजूद उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। ये आंकड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी एजेंसियों से मिले आंकड़ों पर आधारित हैं। चौहान ने उत्पादन में वृद्धि का श्रेय किसानों और मोदी की सरकार की नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि किसान पारंपरिक फसलों से हटकर फल, सब्जियां, फूल, मसाले, बागान फसलों और औषधीय पौधों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं।

शेयर बाजार में टाटा संस की लिस्टिंग पर आरबीआई सख्त

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साफ कर दिया है कि टाटा संस को ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू सभी नियामकीय नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग का नियम भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी को पत्र लिखकर अपना रुख स्पष्ट किया है। आरबीआई ने अपने पत्र में 6 अक्टूबर को टाटा संस की ओर से भेजे गए पत्र का जिक्र किया। कंपनी ने इसमें नियामकीय नियमों के अनुपालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। हालांकि, केंद्रीय बैंक के मुताबिक कंपनी ने किसी विशेष नियम पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा था।

बैंक ऑफ अमेरिका की जारी नई रिपोर्ट ने दुनियाँ को चौंकाया!

किशन सनमुखदास भावनानीं



वैश्विक स्तरपर भारत की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहां एक ओर वैश्विक वित्तीय संस्थान भारतीय विकास की संभावनाओं पर भरोसा जता रहे हैं, दूसरी ओर केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले हासिल करने की बात कर रही है।भारत में आर्थिक बहस अक्सर गरीबों के कल्याण और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के इर्द-गिर्द केंद्रित रहती है। यह आवश्यक भी है,लेकिन मध्यवर्ग और छोटेकारोबारियों की समस्याओं को भी समान गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।यही वर्ग कर भुगतान,उपभोग,बचत, निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आर्थिक विकास की वास्तविक सफ़लता केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों,शेयर बाजार के सूचकांकों अथवा औद्योगिक उत्पादन की तेजी से नहीं मापी जा सकती।इसकी असली कसौटी यह है कि विकास का लाभ गरीब,मध्यम वर्ग,नौकरीपेशा परिवार छोटे व्यापारी, उद्यमी और किसानों तक किस सीमा तक पहुंचता है। इसी व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में 12 नवंबर 2026 का दिन भारत की आर्थिक चर्चा के लिए विशेष महत्व रखता है।

साथियों बात अगर हम बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट : भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर बड़े अनुमान को समझने की करें तो,12 नवंबर 2026 को सामने आए आर्थिक आकलन में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की आर्थिक विकास संबंधी रिपोर्ट की है।बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्चके अर्थशास्त्रियों के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2026- 27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रह सकती है।यह अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती,औद्योगिकगतिविधियों और विनिर्माण क्षेत्र की बेहतर संभावनाओं को रेखांकित करता है।इस अनुमान के पीछे सबसे महत्वपूर्ण आधार औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी है ।विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 8.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.3 प्रतिशत की मजबूती तथा सेवाक्षेत्र की सक्रियता अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। इसके अतिरिक्त बैंक ऋण वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत के आसपास रहने, वाहन बिक्री, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मांग, बिजली की खपत और माल ढुलाई गतिविधियों में मजबूती को भी विकास के सकारात्मक संकेतकों के रूप में देखा गया है।बैंक ऑफ अमेरिका का आकलन यह भी बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी खर्च के सहारे विकास नहीं हो रहा, बल्कि निजी क्षेत्र की गतिविधियां, उपभोग और औद्योगिक निवेश भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतकी विकास संभावनाओं को सकारात्मक माना जा रहा है।एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्पष्टीकरण उपलब्ध प्रकाशित समाचारों में इस आकलन की किसी अलग औपचारिक रिपोर्ट का निश्चित शीर्षक नहीं दिया गया है। इसलिए इसे बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के आर्थिक अनुसंधान संबंधी आकलन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा। साथ ही 7.7 प्रतिशत का आंकड़ा उपलब्ध रिपोर्टिंग में वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी अनुमान के रूप में दर्ज है,अक्टूबर-दिसंबर की तीसरी तिमाही के रूप में नहीं।अत:दोनों अवधियों को एक मानकर प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। साथियों बात अगर हम भारतीय पीएम का संदेश 2047 का इंतजार नहीं, विकसित भारत का लक्ष्य अभी से हासिल करने का संकल्प को समझने की करें तो 12 नवंबर 2026 को भाजपा मुख्यालय में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पीएम ने विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया।उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 की समय- सीमा तक बैठकर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 2047 स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य है, लेकिन देश को विकसित बनाने की दिशा में प्रयास आज से ही निरंतर होने चाहिए।पीएम का यह संदेश केवल राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की व्यापक आवश्यकता की ओर भी संकेत करता है।

राज्यपाल रमेन डेका से विख्यात लेखक डॉ. यतीन्द्र मिश्र ने की सौजन्य भेंट



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से मंगलवार को लोक भवन में विख्यात लेखक एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य डॉ. यतीन्द्र मिश्र ने सौजन्य भेट की। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल उपस्थित थे।

ए.के. गोयल स्कूल में यातायात जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 250 बच्चों की हुई जांच



रायपुर। महादेव घाट में स्थित ए.के. गोयल स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन यातायात विभाग तथा उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल, भाटागांव के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और यातायात नियमों व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। शिविर में करीब 250 बच्चों की जांच की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद स्कूल के डायरेक्टर अशोक अग्रवाल ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। प्राचार्य अजय साहू ने अतिथियों का सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए और आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में उपस्थित एसीपी यातायात सीमा अहिरवार ने बच्चों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए नियमों का पालन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तेलीबांधा यातायात थाना प्रभारी भुनेश्वर साहू ने यातायात नियमों से संबंधित धाराओं के बारे में बताते हुए बच्चों के अनमोल जीवन को सुरक्षित रखने के टिप्स दिए। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे खुद नियम मानें और अपने माता-पिता को भी नियम मानने के लिए प्रेरित करें।

जनजातीय गौरव दिवस पर रायपुर रेलवे मंडल में व्याख्यान एवं लोकनृत्य का आयोजन



रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस पर रायपुर मंडल के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मिक्सड हायर सेकेंडरी स्कूल बीएमवाय में सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा उनके सम्मान में गीत प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष, योगदान एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर भाषण एवं व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों द्वारा जनजातीय संस्कृति, परंपरा एवं विरासत को दर्शाते हुए आकर्षक जनजातीय लोकनृत्य (फोक डांस) की प्रस्तुति दी गई। लोकनृत्य, भाषण एवं व्याख्यान के आयोजन से रेलवे स्कूलों में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें देश की गौरवशाली जनजातीय विरासत से परिचित कराने की पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, कला एवं ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ जनजातीय समाज के उत्थान, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष एवं आदर्शों से अवगत कराने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता एवं कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को भी समझने का अवसर भी मिला।

धान खरीदी में शॉर्टेज पर सरकार श्वेत पत्र जारी करेः भूपेश बघेल

पिछले साल की धान खरीदी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे सरकार



रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने और पिछले साल की खरीदी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। मंगलवार को दिल्ली से रायपुर विमानतल पहुंचे बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आर आई परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई और खरसिया के बोतल्दा रॉक गार्डन की घटना को लेकर तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा, हमने चुनाव आयोग से संपर्क करने की लगातार कोशिश की, लेकिन उनके अड़ियल रवैये और अहंकार की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। बाराखंबा रोड और रामलीला मैदान में हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण ज्ञानेश कुमार की काफी आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ आ गया है कि उनसे जानकारी छिपाई जा रही है और उनका पक्ष जाने बिना ही गलत आदेश जारी कर दिए गए। यह एक सकारात्मक कदम है, और मुझे उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

उन्होंने आगे कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या और अन्य जगहों पर हार का सामना करना पड़ा, और पूरा देश जानता है कि विधानसभा चुनावों को किस तरह से मैनेज किया गया था। अब योगी आदित्यनाथ का दावा है कि स्ट्रक के दौरान हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्हें कैसे पता चला कि 1.37 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं? उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया है?

आरआई पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग

इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने और पिछले साल की खरीदी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं आरआई परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच

आजाद चौक में नए सिटी बस स्टॉप का लोकार्पण

विधायक सुनील सोनी ने महापौर मीनल चौबे के साथ किया भूमिपूजन



रायपुर। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़ सहित ब्राह्मणपारा वार्ड में लगभग 15 लाख रुपये के रोड-नाली-पुलिया आदि के आवश्यक नवीन विकास कार्यों का भूमिपूजन कर शानदार सौगात दी। साथ ही आजाद चौक में नए जीर्णोद्धारित सिटी बस स्टॉप का लोकार्पण भी किया। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर जोन 4 अंतर्गत ब्राह्मणपारा वार्ड क्रमांक 43 क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनहित में जनसुविधा हेतु नाली-रोड-पुलिया आदि के नवीन विकास कार्यों का लगभग 15 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से आजाद चौक ब्राह्मणपारा के समीप पहुंचकर नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौड़ सहित श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर भूमिपूजन करते हुए नागरिकों को एक और शानदार सौगात दी। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने आजाद चौक ब्राह्मणपारा में 2 लाख 30 हजार रुपये की लागत से नवीन जीर्णोद्धारित स्वरूप में सिटी बस स्टॉप का लोकार्पण कर बस यात्रियों एवं नागरिकों को शानदार सौगात दी। विधायक सुनील सोनी ने भूमिपूजन करते हुए नए स्वीकृत विकास कार्यों को ब्राह्मणपारा वार्ड में नियत स्थान पर तत्काल प्रारंभ करवाकर तय समय सीमा के भीतर सतत मॉनिटरिंग करते हुए उच्च स्तरीय गुणवत्ता सहित प्राथमिकता से जनहित में जनसुविधा हेतु पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने स्थल पर नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी एवं कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह को निर्देशित किया।

20 एवं 21 नवम्बर को सजेगा बाल वैज्ञानिकों का राज्य स्तरीय मंच

नवाचारों से दिखाएंगे सतत भविष्य की राह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को नई पहचान देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 20 एवं 21 नवम्बर 2026 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित बाल वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक परियोजनाओं और नवाचारी विचारों का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही विशेषज्ञों के समक्ष अपने शोध, प्रयोगों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना, जिज्ञासा, तार्किक चिंतन और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना है। इस कार्यक्रम में कनिष्ठ वर्ग के अंतर्गत 10 से 14 वर्ष तथा वरिष्ठ वर्ग में 14 वर्ष से अधिक एवं 17 वर्ष तक के बाल वैज्ञानिक भाग लेते हैं। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच बाल वैज्ञानिकों का चयन राज्य स्तरीय आयोजन के लिए किया जाता है।

16 बाल वैज्ञानिक करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व

राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों की वैज्ञानिक परियोजनाओं का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विषय की समझ, नवाचार, अनुसंधान पद्धति और प्रस्तुतिकरण के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। चयनित बाल वैज्ञानिक रायपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और देशभर से आने वाले बाल वैज्ञानिकों के बीच अपनी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे।

करोड़ों की ठगी का आरोपी दीपक टंडन कोर्ट में पेश, तीन दिन का मिला रिमांड

रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपये की कथित ठगी, ब्लैकमेलिंग और धमकी के मामलों में आरोपी होटल कारोबारी दीपक टंडन को रायपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच दीपक टंडन हथकड़ी पहने हंसता नजर आया और उसने मीडिया के सामने थम्स-अप का इशारा भी किया। कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर दीपक टंडन को कमिश्नरेट पुलिस को सौंप दिया है। दीपक टंडन के खिलाफ हाल ही में दर्ज आठवीं एफआईआर में एसईसीएल कोरबा में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती और कोल ट्रांसपोर्टिंग का ठेका दिलाने के नाम पर 56 लाख रुपये लेने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, उनसे क्रमशः 25 लाख



और 31 लाख रुपये लिए गए थे। ठेका नहीं मिलने पर रकम वापस मांगी गई तो कथित तौर पर टालमटोल की गई। भुगतान के लिए दिए गए चेक भी बाउंस हो गए।दीपक टंडन और उसकी पत्नी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और कोरबा में शिकायतें और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस इन मामलों में ठगी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और धमकी से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।

रायपुर में दीपक और पत्नी के खिलाफ पांच एफआईआर

पुलिस के मुताबिक, रायपुर के तेलीबांधा थाने में दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ पांच स्वतंत्र एफआईआर दर्ज हैं। इनमें ठेका दिलाने, जमीन और रेस्टोरेंट बेचने, लग्जरी कार बेचने तथा होटल पर कब्जा बनाए रखने जैसे आरोप शामिल हैं। एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि VIP रोड स्थित साधना मंडप (होटल वेलकम श्री) की लीज समाप्त होने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया। नगर निगम की सील तोड़ने, जबरन प्रवेश करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। इस मामले में पत्नी बरखा टंडन का नाम भी शामिल है।

137 कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचाना अनिवार्य

ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई, मूल्य सूची लगाना होगा

रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा दवा विक्रेताओं, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं कैंसर उपचार संस्थानों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से इन दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन) लागू किया गया है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में संशोधन का लाभ मरीजों तक पहुँचाना है। संबंधित संस्थानों को एनपीपीए द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधि कंपनियों की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार

9 नवंबर से लागू हुई नई एमआरपी, अस्पतालों और दवा दुकानों को मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश

दवाओं का विक्रय सुनिश्चित करना होगा। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों एवं चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित मूल्य सूची अथवा पूरक मूल्य सूची अपने परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करें, जहाँ मरीज एवं उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें। जहाँ लागू हो, यह सूची संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाए। अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों को उनके यहाँ उपलब्ध तथा मरीजों को दी जाने वाली संबंधित कैंसर रोधी दवाओं की एमआरपी का संशोधित मूल्य सूची से नियमित मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मरीज से लागू संशोधित एमआरपी से अधिक राशि नहीं ली जा सकती।

साथ ही, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी की स्थिति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

स्वच्छता में नंबर-1 का पुरस्कार लेने दिल्ली गए, रायपुर में छोड़ गए गंदगी का ढेरः नेताप्रतिपक्ष



रायपुर। रायपुर नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में उपलब्धि मिलने पर विपक्ष सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि स्वच्छता में नंबर-1 का पुरस्कार लेने दिल्ली गए लेकिन रायपुर में गंदगी का ढेर छोड़ गए। रायपुर नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। लोगों के घरों से कचरा नियमित रूप से नहीं उठ रहा है। मोहल्लों से निकलने वाले कचरे को समय पर नहीं उठाया जा रहा है। नुक्कड़ों से कचरा उठाने के लिए तरह-तरह के बहाने बताए जा रहे हैं। सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई हो नहीं पा रही है अधिकारी और महापौर अपने- अपने कार्यों में मस्त हैं, आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि महाराज बंध तालाब के पास जहां स्वयं उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री जाते हैं, वहीं पर गंदगी का आलम है। क्या यही हमारे राजधानी रायपुर की वास्तविक स्थिति है? शहर के लिए गौरव की बात कही जा रही है।

खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख की सामग्री जब्त

बिना लाइसेंस के बन रहे थे ब्यूटी क्रीम-फेशियल सीरम



रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर की टीम ने बिना वैध निर्माण अनुज्ञप्ति के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करने वाली फर्म के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने महावीर नगर स्थित मेसर्स शिव बाबा इंटरनेशनल का औचक निरीक्षण कर लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की है। यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल (आईएएस) के निर्देशानुसार एवं सहायक औषधि नियंत्रक बेनी राम साहू के मार्गदर्शन में की गई।

निरीक्षण के दौरान फर्म के संचालक महेंद्र सबदेव द्वारा बिना वैध निर्माण अनुज्ञप्ति के विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर ग्लैमरिक्स ब्यूटी क्रीम, मॉम ब्यूटी व्हाइटनिंग क्रीम और क्रीनज पर्ल फेशियल सीरम का निर्माण किया जा रहा था। टीम ने इन तीनों उत्पादों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए लिए। साथ ही निर्मित उत्पादों सहित निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही 12 प्रकार की मशीनें, 8 प्रकार के पैकेजिंग कार्टन एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। जब्त नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में औषधि नियंत्रण अधिकारी टेकचंद धिरेठ, ईश्वरी नारायण सिंह, लक्ष्मी कौशिक एवं सुरेश साहू शामिल रहे।

संदिग्ध कॉस्मेटिक उत्पादों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी- खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय निर्माता का नाम, पता, निर्माण अनुज्ञप्ति संबंधी विवरण एवं उपयोग की अंतिम तिथि की जांच अवश्य करें। बिना वैध अनुज्ञप्ति के कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण एवं विक्रय की जानकारी मोबाइल नंबर 9340597097 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अवैध रूप से कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

नर्सिंग ऑफिसर्स का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज से

10 मेडिकल कॉलेजों में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना, नियमितीकरण की मांग प्रमुख



रायपुर। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन 18 नवंबर से आरम्भ हो रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सेज 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज के कैंपस में यह आंदोलन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। संघ की प्रमुख मांग 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना और संविदा स्टाफ, डेली वेजेस स्टाफ और एनएचएम स्टाफ के नियमितीकरण की मांग है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से नर्सेज की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत नर्सेज लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी प्रमुख मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत ने बताया कि सभी 10 मेडिकल कॉलेजों के कैंपस में एक साथ यह आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के दौरान नर्सेज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.